website: www.royalpatrika.com
G-mail: royalpatrika@gmail.com
Yahoo: royal_patrika@yahoo.com

R.N.I. No. RAJHIN/2012/48736

दैनिक
रॉयल पत्रिका

वर्ष : 13 | अंक : 298 | पेज: 8 | जयपुर, रविवार 05 अक्टूबर 2025 | मूल्य: 1.50 रुपये

पीएम मोदी ने आईटीआई टॉपर्स को किया सम्मानित

-बिहार समेत युवाओं के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) के टॉपर्स को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने आईटीआई छात्रों के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित करने की परंपरा शुरू की थी। आज, हम इस गौरवशाली परंपरा का एक और अध्याय देख रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मैं भारत के कोने-कोने से हमारे साथ जुड़ने वाले सभी युवा आईटीआई छात्रों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह समारोह इस बात का प्रतीक है कि भारत अब कौशल विकास को कितना महत्व देता है। आज देश भर के युवाओं के लिए दो और बड़ी शिक्षा एवं कौशल विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है।" प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दीक्षांत समारोह के पीछे का विचार यही था कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ज्ञान और कौशल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

आईटीआई न सिर्फ औद्योगिक शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भर भारत की कार्यशालाएं भी हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है। बिहार उन राज्यों में से एक है, जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा हैं। इसलिए बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है तो स्वभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण को समर्पित एक विशाल आयोजन हो रहा है। यह दर्शाता है कि एनडीए सरकार बिहार के युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की युवा-केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 60 हजार करोड़ रुपए के निवेश से देशभर में एक हजार सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए 'पीएम-सेतु' का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने खासकर बिहार को योजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने संशोधित 'मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता' योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत दो साल के लिए 5 लाख स्नातकों को एक हजार रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया गया। बिहार के चार विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा बिहटा में एनआईटी पटना के नए परिसर का उद्घाटन किया गया।

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिया आंध्र प्रदेश के ऑटो चालकों को तोहफा

-जल्द नए राइड बुकिंग ऐप की भी घोषणा

आंध्र प्रदेश (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को 'ऑटो चालक सेवालो' योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक ऑटो चालक को 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में ऑटो चालकों के लिए ओला-उबर जैसे नए सरकारी ऐप की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में 'ऑटो चालक सेवालो' कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान घोषणा की कि राज्य सरकार रैपिडो और उबर की तरह एक नया राइड बुकिंग ऐप लॉन्च करेगी, जिसका उद्देश्य पूरे आंध्र प्रदेश में ऑटो चालकों को सशक्त बनाना है। ऐप के साथ-साथ उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जल्द ही एक ऑटो चालक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद ऑटो में सवारी की। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी मौजूद थे, जो ऑटो में बैठकर ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे थे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "गठबंधन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत हमने एक और

योजना शुरू की है। पिछले चुनाव में किए गए वादे के अनुसार, मुझे 'ऑटो चालक सेवा' योजना के माध्यम से प्रत्येक ऑटो चालक के खाते में 15,000 रुपए जमा करते हुए खुशी हो रही है। इस योजना के माध्यम से हमने 2,90,669 ऑटो और कैब चालकों को 436 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।" अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, "जनता के आशीर्वाद से पिछले 15 महीनों में कल्याण में कोई कमी नहीं आई है। विकास में कोई रुकावट नहीं आई है। इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। मैं घोषणा करता हूं कि हम जनता के आशीर्वाद के साथ राज्य के विकास के लिए और भी अच्छे कार्यक्रम शुरू करने के लिए आगे बढ़ेंगे।" इस बीच, विजयवाड़ा में 'जन सेना' पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की तस्वीरों का दुग्धाभिषेक किया। ' जन सेना' पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए विजयवाड़ा में एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां दोनों नेताओं की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया।

'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' के तहत 6.5 करोड़ लाख महिलाओं ने कराई स्वास्थ्य जांच

-जेपी नड्डा ने इसे बताया ऐतिहासिक

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस (17 सितंबर) पर शुरू किए गए 'स्वस्थ

नारी, सशक्त परिवार' अभियान के तहत देशभर में आयोजित लगभग 18 लाख स्वास्थ्य शिविरों में 6 करोड़ 50 लाख महिलाओं ने स्वास्थ्य जांच कराई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस अभियान को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

देशभर में कुल 18 लाख स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए

17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशभर में कुल 18 लाख स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 6 करोड़ 50 लाख महिलाओं ने हेल्थ चेकअप कराया और डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया। यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

जेपी नड्डा ने एक्स पर कहा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' का जिक्र करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर को शुरू किया गया। दो सप्ताह तक चलने वाला 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान, देशभर में आयोजित लगभग 18 लाख स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 6 करोड़ 50 लाख महिलाओं की जांच के ऐतिहासिक पड़ाव को पार कर लिया है। यह अभियान 2 अक्टूबर को संपन्न हुआ। जेपी नड्डा ने कहा कि यह असाधारण उपलब्धि महिलाओं के स्वास्थ्य को सुदृढ़ परिवारों और समृद्ध समुदायों के केंद्र में रखने के राष्ट्र के सामूहिक संकल्प को दर्शाती है। आइए, हम प्रत्येक महिला को अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने, नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और एक स्वस्थ, सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करके इस गति को जारी रखें।

पीएम मोदी ने अभियान की सराहना की

इस अभियान के तहत गुजरात, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आयोजित इन शिविरों में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान की जमकर सराहना की। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री लगातार उनके हित में कार्य कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य की चिंता करना इस बात का प्रमाण है। महिलाओं ने ने कहा, "हमें गर्व है कि पीएम मोदी हमारे स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए इतने समर्पित हैं।

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 :

निषाद कुमार और सिमरन ने भारत को दिलाए दो स्वर्ण पदक

नई दिल्ली (एजेंसी)। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में चल रही विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में आज

शुक्रवार का दिन भारत के लिए बेहद खास रहा। भारत के निषाद कुमार और सिमरन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद टी-47 स्पर्धा में और सिमरन ने महिलाओं की 100 मीटर टी-12 स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। भारत ने इन दो स्वर्ण पदकों की बदौलत पदक तालिका में बड़ा उछाल लगाया और 11वें स्थान से सीधे चौथे स्थान पर पहुंच गया। मौजूदा पदक तालिका में ब्राजील 12 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य के साथ पहले, चीन 9 स्वर्ण, 16 रजत और 13 कांस्य के साथ दूसरे और पोलैंड 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत अब तक कुल 15 पदक जीत चुका है, जिसमें 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। इससे पहले भारत की प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर टी-36 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जबकि प्रदीप कुमार ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो एफ-46 स्पर्धा में एक और कांस्य पदक दिलाया।

निषाद कुमार ने ऊंची कूद में शानदार प्रदर्शन करते हुए तुर्किये के अब्दुल्ला इल्गाज और अमेरिका के तीन बार के चैंपियन रोडरिक टाउनसेंड को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 2.18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इल्गाज ने 2.08 मीटर की कूद लगाकर यूरोपीय रिकॉर्ड हासिल किया, लेकिन निषाद ने उन्हें पछाड़ दिया। वहीं, टाउनसेंड केवल 2.03 मीटर तक ही कूद पाए और बाहर हो गए। महिलाओं की 100 मीटर टी-12 स्पर्धा में सिमरन ने गाइड उमर सैफी के साथ शानदार तालमेल दिखाया। उन्होंने पहले सेमीफाइनल में 12.08 सेकंड का समय निकाला और पहली बार फाइनल में 12 सेकंड की बाधा तोड़ते हुए 11.95 सेकंड में दौड़ पूरी की। यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। भारत के खिलाड़ियों ने घरेलू दर्शकों के सामने दबाव में भी संयम बनाए रखा और देश का नाम रोशन किया। इन जीतों के साथ भारत के पदक जीतने का सिलसिला और तेज हो गया है।

चुनाव आयोग ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

- भाजपा ने एक या दो चरणों में चुनाव कराने की मांग रखी

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को चुनाव आयोग ने बिहार के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनके साथ चर्चा की। इस दौरान सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव और मांग को चुनाव आयोग के सामने रखा।

भाजपा ने चुनाव आयोग के सामने 16 सूत्री मांग और सुझाव रखे हैं। बैठक के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा ने एक या दो चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। भाजपा ने इस दौरान मतदाता सूची की तैयारी पारदर्शी एवं बेहतर तरीके से करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को बधाई दी।

भाजपा ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र धार्मिक स्थलों में स्थित हैं। बार-बार आयोग को इस संबंध में निवेदन करने के बाद भी इन मतदान केंद्रों को नहीं बदला जा रहा है। ये सभी मतदान

केंद्र आज से 30 वर्ष पूर्व से बने हुए हैं। पहले इन इलाकों में कोई भी सरकारी भवन एवं स्कूल-कॉलेज नहीं हुआ करते थे। अब सभी जगहों पर मतदाताओं के निकट स्कूल और कॉलेज हो गए हैं। चुनाव के पूर्व इन सभी मतदान केंद्रों की जांच कर नए सरकारी भवन में मतदान केंद्र बनाने की मांग रखी है।

भाजपा ने मतदाताओं को चुनाव प्रारंभ होते ही वोटर स्लिप सही तरीके से बांटने की मांग की है ताकि मतदाता उसे लेकर मतदान केन्द्र पर पहुंच सकें। भाजपा ने चुनाव के एक दिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च कराने की भी मांग रखी तथा चुनाव के दिन जिला और विधानसभा क्षेत्र का बोर्डर सील कराने की मांग की। भाजपा ने स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान केन्द्र पर किसी भी तरह के ढके हुए चेहरे वाले मतदाताओं के चेहरे का मिलान स्वीकृत पहचान पत्र से करने और पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही उन्हें मतदान की अनुमति देने की बात की है।

'नवरंग' फेम अभिनेत्री संध्या शांताराम का निधन

-87 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली (एजेंसी)। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर आई। मशहूर अभिनेत्री और वी. शांताराम की तीसरी पत्नी संध्या शांताराम का निधन हो गया है। उन्होंने 87 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वह अभिनय के साथ ही अपने डांस के लिए भी जानी जाती थी। संध्या शांताराम का अंतिम संस्कार शनिवार को शिवाजी पार्क स्थित वैकुंठ धाम में किया गया।

महाराष्ट्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक मामलों के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यह जानकारी दी। उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए आशीष शेलार ने लिखा, "फिल्म 'पिंजरा' की प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम के निधन की खबर बेहद दुखद है। उन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में अपने अद्भुत अभिनय और नृत्य कौशल से दर्शकों पर एक अनूठी छाप छोड़ी। फिल्म 'झनक झनक पायल बाजे,' 'दो आंखें बारह हाथ,' और खासकर 'पिंजरा' में उनकी अमर भूमिका दर्शकों के दिलों में हमेशा

याद रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें!" संध्या शांताराम को मराठी और हिंदी में अपने शानदार अभिनय और कुशल नृत्य के लिए जाना जाता था। वह मशहूर फिल्मकार वी. शांताराम की तीसरी पत्नी थीं। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी जयश्री से तलाक लेने के एक महीने बाद ही संध्या से शादी कर ली। दोनों ने फिल्म 'पिंजरा' में साथ काम किया था। हालांकि संध्या ने अधिक फिल्में नहीं की हैं, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा की कुछ यादगार फिल्मों के लिए जाना जाता है। वी. शांताराम ने 1951 में अपनी फिल्म 'अमर भूपाली' के लिए नई प्रतिभाओं की तलाश के दौरान संध्या की प्रतिभा को पहचाना था। फिल्म निर्माता को उनकी मनमोहक आवाज ने प्रभावित किया था। इस फिल्म में संध्या ने एक सिंगर का रोल प्ले किया था।

उन्हें 'झनक झनक पायल बाजे', 'दो आंखें बारह हाथ', 'नवरंग', 'पिंजरा' और 'अमर भूपाली' जैसी फिल्मों के लिए आज भी याद किया जाता है। फिल्म 'झनक झनक पायल बाजे' में वह गोपी कृष्ण के साथ दिखाई दी थीं। इस फिल्म के लिए गोपी ने ही उन्हें डांस सिखाया। फिल्म ने बाद में चार फिल्मफेयर पुरस्कार अपने नाम किए थे।

केजरीवाल का सीएम हाउस बनेगा गेस्ट हाउस

दिल्ली। दिल्ली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक बंगले (6, फ्लैग रोड) को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, इसमें पार्किंग स्पेस, कैफेटेरिया, वेटिंग हॉल, मीटिंग रूम और अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी। यहां अधिकारी और मंत्री किराया देकर रुक सकेंगे, जबकि आम जनता को पारंपरिक भोजन का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। अरविंद केजरीवाल साल 2015 से 2024 तक पूरे नौ साल अपने परिवार के साथ इसी बंगले में रहे थे। रेनोवेशन पर खर्च हुए 45 करोड़ को भाजपा ने "शीशमहल" कहा था।

अमित शाह ने 900 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नई आपराधिक कानूनों पर राज्य-स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन और लगभग 900 करोड़ रुपये के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान अमित शाह ने बताया कि राज्य सरकार ने चार परियोजनाओं का उद्घाटन और आठ परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जो केंद्र और राज्य की विकास प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमित शाह ने नई आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सराहना करते हुए कहा कि यह भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार है। उन्होंने बताया कि ये कानून 1 जुलाई 2024 को ब्रिटिश काल के पुराने कानूनों की जगह लागू किए गए और यह दंडात्मक प्रणाली से न्याय-उन्मुख प्रणाली की ओर बदलाव दर्शाते हैं, जिससे हर नागरिक, विशेषकर गरीबों, के

अधिकार सुनिश्चित होते हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के परिणाम पहले ही दिखाई देने लगे हैं। हरियाणा में सजा दर 40% से बढ़कर 80% से अधिक हो गई है। ई-एफआईआर, जीरो एफआईआर, जब्तियों का अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग और गंभीर अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जांच जैसी व्यवस्थाओं ने पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत की है। पहली बार आतंकवाद, संगठित अपराध और भीड़ द्वारा हिंसा की परिभाषाएं शामिल की गई हैं और पुलिस, न्यायपालिका और अभियोजन के लिए समयसीमा तय की गई है। शाह ने कहा कि लागू होने के एक साल में पूरे देश में 53% एफआईआर में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की गई, जबकि हरियाणा में यह आंकड़ा 71% है, जो शुरुआती सफलता को दर्शाता है। गृह मंत्रालय ने 14.8 लाख पुलिसकर्मियों, 42,000 जेल अधिकारियों, 19,000 कोर्ट स्टाफ और 11,000 अभियोजकों को इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया है। विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए शाह ने हरियाणा सरकार के शासन मॉडल की सराहना की और कहा कि अब राज्य में नौकरी भर्ती योग्यता के आधार पर होती है, न कि "खर्ची या पर्ची" के आधार पर। उन्होंने कहा कि आज उद्घाटित परियोजनाएं हरियाणा के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूती देंगी। अमित शाह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में राष्ट्रीय प्रयास की भी अपील की और दिवाली पर केवल भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प लेने की बात कही। उन्होंने कहा, "यदि 140 करोड़ भारतीय केवल भारत में बने उत्पाद खरीदते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और 2047 तक भारत हर क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व में होगा।"

रॉयल पत्रिका

संपादकीय....

रिज़र्व बैंक के सुधार पैकेज से बैंकिंग, कॉर्पोरेट ऋण और पूंजी बाज़ार को नई दिशा

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय ऐसे दौर से गुजर रही है, जब उसे निवेश, पारदर्शिता और स्थिरता की नई दिशा देने की आवश्यकता है। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बुधवार को व्यापक सुधार पैकेज की घोषणा की है, जिसे बीते एक दशक में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह सुधार पैकेज केवल बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती देने वाला नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट ऋण प्रणाली, पूंजी बाज़ार और वित्तीय पारदर्शिता की संरचना को भी नया आकार देने की क्षमता रखता है। रिज़र्व बैंक के इन उपायों का सबसे अहम लक्ष्य यह है कि कंपनियों तक सस्ता और आसान ऋण पहुँच सके। अब तक बैंक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के कॉर्पोरेट ऋण पर कठोर नियम लागू करते थे, जिनके चलते ऋण महंगा हो जाता था और कई बार बड़े उद्योगों को पूंजी जुटाने में मुश्किलें आती थीं। नई व्यवस्था में इन बाधाओं को हटाते हुए बैंकों को अधिक लचीलापन दिया गया है। इससे न केवल कंपनियों की पूंजी लागत घटेगी, बल्कि बैंकिंग सेक्टर पर अनावश्यक बोझ भी कम होगा। नई घोषणा का दूसरा बड़ा पहलू यह है कि अब पूंजी बाज़ार को भी अतिरिक्त ऊर्जा मिलने वाली है। आईपीओ फाइनेंसिंग की सीमा पहले 10 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। यह बदलाव उन निवेशकों के लिए खासतौर पर राहतकारी है, जो नए शेयर इश्यू में हिस्सा लेना चाहते हैं। इसी तरह शेयरों पर ऋण की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दी गई है। इसका सीधा असर यह होगा कि निवेशक बड़ी मात्रा में निवेश कर पाएंगे और कंपनियों को भी पूंजी जुटाने में आसानी होगी। रिज़र्व बैंक का एक और साहसिक कदम सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज) पर ऋण की सीमा को पूरी तरह हटा देना है। यह बदलाव कॉर्पोरेट जगत और निवेशकों, दोनों को नया सहारा देगा। कंपनियाँ अब अपनी लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज के आधार पर अधिक पूंजी जुटा पाएंगी और निवेशकों के लिए भी निवेश का दायरा बढ़ेगा। इससे भारतीय वित्तीय बाज़ार अधिक गहराई और मजबूती हासिल करेगा। इन सुधारों का असर केवल घरेलू स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। जब कॉर्पोरेट ऋण सस्ता होगा, पूंजी बाज़ार अधिक पारदर्शी होगा और निवेशकों को सुरक्षा व भरोसा मिलेगा, तो भारत में विदेशी निवेशक भी अधिक आकर्षित होंगे। यह सीधे-सीधे रुपए की मज़बूती और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में भारत की साख को बेहतर करेगा। वैश्विक मंच पर यह संदेश जाएगा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को निवेश और पारदर्शिता की नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। पिछले कई वर्षों से देश में यह शिकायत बनी हुई थी कि ऋण की पहुँच सीमित है और कॉर्पोरेट जगत को पूंजी की ज़रूरत पूरी करने के लिए महंगे विकल्प अपनाने पड़ते हैं। ऐसे में रिज़र्व बैंक का यह सुधार पैकेज निश्चित रूप से एक ताज़ी हवा का झोंका है।

"अमरीकी शटडाउन संकट: क्यों भारत का लोकतंत्र अधिक व्यावहारिक और जनता-केंद्रित साबित होता है"

-अमेरिकी लोकतंत्र की कमजोरी उजागर करता शटडाउन

लोकतंत्र को दुनिया में सबसे लोकप्रिय और स्वीकृत शासन व्यवस्था माना जाता है। भारत और अमरीका दोनों ही देशों को आधुनिक लोकतंत्र के अग्रणी उदाहरण माना जाता है। लेकिन दोनों देशों की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में मूलभूत अंतर है। अमरीका का संघीय लोकतंत्र जहां राष्ट्रपति और संसद के बीच शक्ति संतुलन पर आधारित है, वहीं भारत का संसदीय लोकतंत्र कार्यपालिका और विधायिका को आपसी तालमेल के साथ काम करने का अवसर देता है। यही कारण है कि अमरीका समय-समय पर "शटडाउन" जैसे संकटों का सामना करता है, जबकि भारत में इस तरह की स्थिति लगभग असंभव है। अमरीका में वर्तमान में जो समस्या सामने आई है, उसे शटडाउन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि संसद और राष्ट्रपति प्रशासन बजट को तय समय पर पारित नहीं कर पाते, तो सरकार के पास खर्च करने के लिए धन उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में गैर-जरूरी सरकारी सेवाएं पूरी तरह बंद हो जाती हैं और लाखों कर्मचारी प्रभावित होते हैं। यह स्थिति न केवल राजनीति बल्कि अर्थव्यवस्था और जनता के दैनिक जीवन पर गहरा असर डालती है। यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या भारत में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? यदि नहीं, तो इसके पीछे कौन से संवैधानिक और संस्थागत कारण हैं? इन सवालों के जवाब हमें भारतीय लोकतंत्र की व्यावहारिकता और स्थायित्व की गहराई से समझ प्रदान करते हैं।

अमरीकी शटडाउन की पृष्ठभूमि

अमरीका में संघीय सरकार का खर्च कांग्रेस द्वारा पारित बजट से चलता है। वहां की प्रणाली में राष्ट्रपति और कांग्रेस, दोनों को मिलकर बजट पारित करना होता है। यदि किसी कारण से कांग्रेस (सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स) और राष्ट्रपति में सहमति नहीं बनती, तो सरकार का खर्च बाधित हो जाता है। अमरीका में "शटडाउन" शब्द इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि बजट पारित न होने की स्थिति में सरकारी संस्थाएं एकदम से ठप हो जाती हैं। यह समस्या वहां की प्रेसिडेंशियल सिस्टम की देन है, जहां राष्ट्रपति और संसद दो अलग-अलग शक्तियों के रूप में कार्य करते हैं और दोनों का कार्यकाल स्वतंत्र होता है। इतिहास गवाह है कि अमरीका में शटडाउन की स्थिति बार-बार उत्पन्न हुई है। कभी रिपब्लिकन और कभी डेमोक्रेट्स ने बजट को लेकर अड़ंगा डाला। राजनीतिक सहमति के अभाव में कई बार सरकारी कामकाज हफ्तों तक ठप रहा है। 2018-19 का शटडाउन तो 35 दिनों तक चला था, जो अमरीका के इतिहास में सबसे लंबा था।

शटडाउन का प्रत्यक्ष प्रभाव

शटडाउन का असर तुरंत लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ता है। सरकारी कर्मचारी: हजारों कर्मचारी महीनों तक बिना वेतन के घर बैठने को मजबूर हो जाते हैं। सेवाओं पर असर: राष्ट्रीय उद्यान, म्यूजियम, पर्यटन केंद्र और कई प्रशासनिक दफ्तर बंद हो जाते हैं। आर्थिक दबाव: कर्मचारियों की आय रुकने से उनकी क्रयशक्ति घट जाती है। नतीजतन बाजार में मांग कम होती है, जिससे उत्पादन और व्यापार पर असर पड़ता है। उद्योग और तकनीक क्षेत्र: नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आवश्यक सरकारी अनुमतियां और लाइसेंस समय पर नहीं मिल पाते। पर्यटन और हवाई यात्रा: इन क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च तुरंत घट

जाता है। बैंकिंग व वित्तीय संस्थान: ऋण और निवेश पर दबाव बढ़ जाता है। इस प्रकार, शटडाउन सिर्फ प्रशासनिक व्यवधान नहीं बल्कि संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाला संकट बन जाता है।

अमेरिकी लोकतंत्र की कमजोरी उजागर करता शटडाउन

शटडाउन से अमरीकी लोकतंत्र की एक बड़ी कमजोरी सामने आती है – सहमति बनाने की क्षमता का अभाव। राजनीतिक ध्रुवीकरण: अमरीका में दो प्रमुख दल (डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन) हैं, और इनके बीच अक्सर गहरी वैचारिक खाई होती है। बजट जैसे बुनियादी विषय पर भी सहमति कठिन हो जाती है। संवैधानिक ढांचा: राष्ट्रपति और कांग्रेस के कार्यकाल स्वतंत्र होते हैं। यदि कांग्रेस में विपक्षी दल बहुमत में है, तो वह राष्ट्रपति को लगातार चुनौती देता है। जनता पर बोझ: राजनीतिक असहमति का खामियाजा आम जनता और कर्मचारी भुगतते हैं। आर्थिक अनिश्चितता: हर शटडाउन अमेरिकी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा करता है। यह दिखाता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से मजबूत नहीं होता, बल्कि उसकी संस्थागत संरचना और राजनीतिक संस्कृति भी बेहद महत्वपूर्ण होती है।

भारतीय लोकतंत्र की व्यावहारिकता

अब प्रश्न उठता है कि भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में ऐसा संकट क्यों नहीं आता? इसका उत्तर भारतीय लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली और संवैधानिक ढांचे में निहित है।

संसदीय व्यवस्था का लाभ: भारत में कार्यपालिका (सरकार) और विधायिका (संसद) एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। इस कारण सरकार के पास संसद का विश्वास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि सरकार का बहुमत संसद में नहीं है, तो वह टिक ही नहीं सकती। इसीलिए बजट पारित न होने की स्थिति में सरकार स्वतः गिर जाएगी और नई सरकार बनेगी।

निरंतरता की गारंटी: भारत में बजट समय पर पारित नहीं होने पर भी "वोट ऑन अकाउंट" या "अनुदान मांग" जैसे विकल्प मौजूद हैं। इनके माध्यम से सरकार आवश्यक खर्चों को जारी रख सकती है। अतः सरकारी कामकाज रुकता नहीं है।

मजबूत नौकरशाही तंत्र: भारतीय प्रशासनिक तंत्र निरंतरता बनाए रखने में सक्षम है। चाहे राजनीतिक असहमति हो, लेकिन आम जनता को मिलने वाली सेवाएं नहीं रुकतीं।

संघीय संरचना में संतुलन: भारत का संघीय ढांचा अमरीका की तरह कठोर नहीं है। यहां केंद्र को वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टि से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। इससे सरकार के पास योजनाओं को लागू करने की क्षमता बनी रहती है।

तुलनात्मक दृष्टि : अमरीका बनाम भारत

बिंदु	अमरीका	भारत
शासन प्रणाली	राष्ट्रपति प्रणाली	संसदीय प्रणाली
कार्यपालिका और विधायिका	स्वतंत्र	परस्पर जुड़ी
बजट पारित न होने पर	शटडाउन, सेवाएं ठप	सरकार गिर जाती है, नई सरकार बनती है
नागरिक सेवाओं पर असर	सीधे बंद	निरंतर जारी
राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रभाव	बेहद गहरा	तुलनात्मक रूप से कम

शटडाउन से भारत के लिए सबक

भारत को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच सहयोग और संवाद कितना जरूरी है। हालांकि भारत की प्रणाली में शटडाउन जैसी स्थिति नहीं आती, लेकिन राजनीतिक गतिरोध और टकराव से विकास कार्य धीमे हो सकते हैं। संसद का सुचारू संचालन होना चाहिए। बजट पर सार्थक बहस हो, लेकिन समय पर पारित करना आवश्यक है। राजनीतिक दलों को जनता की बुनियादी सेवाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की छवि

अमरीका के बार-बार होने वाले शटडाउन से यह संदेश जाता है कि वहां की व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है। इसके विपरीत भारत का लोकतंत्र अधिक स्थिर, व्यवहारिक और जनता के लिए भरोसेमंद प्रतीत होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 90 करोड़ से अधिक मतदाता चुनाव में भाग लेते हैं। यहां की प्रणाली ने स्वतंत्रता के बाद अनेक संकटों का सामना किया।

चिंताजनक है बढ़ते सड़क हादसों की भयावह तस्वीर

-हादसे रोकने के लिए आमजन का सहयोग जरूरी

गिलास आधा खाली है या आधा भरा, यह अवधारणा हर किसी ने अपने-अपने हिसाब से समझी है। सच यही है कि दोनों ही परिस्थितियां मौजूद हैं। सड़क सुरक्षा के मामले में भी यही स्थिति है। देश और प्रदेश में कहीं सड़क हादसों पर अंकुश की कोशिशें होती हैं तो कहीं नई नीतियां और तकनीकें अपनाई जाती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हादसे घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2023 रिपोर्ट राजस्थान की सड़क सुरक्षा की भयावह तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में हर 44 मिनट में एक व्यक्ति सड़क हादसे में जान गंवा रहा है। यह स्थिति केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवारों की तबाही, सपनों के टूटने और समाज पर बढ़ते बोझ की असलियत है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि राजधानी जयपुर सड़क हादसों में प्रदेशभर में नंबर वन है। जब राजधानी जैसी आधुनिक और संसाधनयुक्त जगह हादसों में सबसे आगे है, तो ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की स्थिति सहज ही समझी जा सकती है।

सड़क हादसों की भयावह तस्वीर

सड़क हादसे अब एक राष्ट्रीय आपदा जैसे बन चुके हैं। भारत में हर साल लाखों लोग इन हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। राजस्थान की तस्वीर और भी डरावनी है – हर 44 मिनट में एक मौत, हजारों लोग स्थायी रूप से अपाहिज हो जाते हैं, सैकड़ों परिवार आर्थिक और मानसिक संकट में घिर जाते हैं। आंकड़ों की जटिलता से परे यह समझना जरूरी है कि एक सड़क हादसे का असर केवल पीड़ित तक सीमित नहीं रहता। उसका परिवार, उसका भविष्य और उसके आश्रित सभी प्रभावित होते हैं।

सड़क हादसों के पीछे प्रमुख कारण

हादसों के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से कुछ सामाजिक व्यवहार से जुड़े हैं और कुछ संरचनात्मक खामियों से।

सड़क और बुनियादी ढांचे की खामियां: कई सड़कें टूटी-फूटी या गड्ढों से भरी हुई हैं। हाइवे पर डिवाइडर और साइनबोर्ड का अभाव। ग्रामीण सड़कों पर स्ट्रीट लाइट और स्पीड ब्रेकर नहीं होते।

बरसात में पानी भरने से सड़कें खतरनाक हो जाती हैं।

वाहन चालकों की लापरवाही: ओवरस्पीडिंग और बिना वजह ओवरटेकिंग आम है। शराब या नशे की हालत में गाड़ी चलाना। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न करना। मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना।

प्रशासनिक कमियां: ट्रैफिक पुलिस की निगरानी सीमित है। चालान की कार्रवाई कई बार औपचारिक रह जाती है। पुराने वाहन बिना फिटनेस टेस्ट के सड़कों पर दौड़ते हैं। ट्रॉमा सेंटर और एम्बुलेंस सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं होतीं।

सामाजिक उदासीनता: लोग दुर्घटना पीड़ित की मदद करने से कतराते हैं। आमजन में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता का अभाव है। समाज इसे प्रशासन की जिम्मेदारी मानकर अपने हिस्से की भूमिका निभाने से बचता है।

हादसों के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

सड़क हादसा केवल जान जाने तक सीमित नहीं होता। इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव गहरे होते हैं – परिवार की तबाही : कमाने वाले सदस्य की मौत परिवार को आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से तोड़ देती है। आर्थिक नुकसान : इलाज का खर्च, रोजगार का नुकसान और जीवनभर की परेशानियां। राष्ट्रीय हानि : देश की उत्पादन क्षमता और श्रमशक्ति पर सीधा असर। सामाजिक तनाव : विकलांग होने पर व्यक्ति समाज पर बोझ समझा जाने लगता है।

सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी

सरकार और प्रशासन सड़क हादसों को रोकने के लिए कई स्तरों पर कदम उठा सकते हैं – सड़क निर्माण और मरम्मत, गड्ढों और टूटी सड़कों को तुरंत ठीक करना। हाइवे और ग्रामीण सड़कों पर संकेतक, डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट लगाना।

ट्रैफिक प्रबंधन: सीसीटीवी और स्पीड राडार का उपयोग। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल और ऑटोमैटिक चालान प्रणाली।

कड़े नियम और दंड: शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों पर भारी जुर्माना। पुराने वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य।

मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर: हर जिले में ट्रॉमा सेंटर स्थापित करना। एम्बुलेंस की त्वरित उपलब्धता। 'गोल्डन आवर' में इलाज सुनिश्चित करना।

आमजन की भूमिका

हादसे रोकना केवल प्रशासन का काम नहीं है। समाज का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। सड़क नियमों का पालन : हेलमेट, सीट बेल्ट, स्पीड लिमिट। सामाजिक जिम्मेदारी : दुर्घटना पीड़ित की मदद करना। जागरूकता अभियान : स्कूल, कॉलेज और गांवों में सड़क सुरक्षा शिक्षा। स्वअनुशासन : शराब पीकर गाड़ी न चलाना, मोबाइल का उपयोग न करना।

राजस्थान में हालात क्यों ज्यादा गंभीर?

राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां हादसों को और जटिल बना देती हैं – लंबी और चौड़ी हाइवे सड़कें जहां ओवरस्पीडिंग आम है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव। पर्यटन राज्य होने से यातायात का दबाव अधिक। पुलिस बल और संसाधन सीमित।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव और सीख

कई देशों ने सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। स्वीडन में "Vision Zero" नीति के तहत सड़क डिजाइन, ट्रैफिक शिक्षा और कानून व्यवस्था पर जोर दिया गया। जापान में ड्राइवर प्रशिक्षण और फिटनेस टेस्ट बेहद कड़े हैं। अमेरिका में हाईवे पेट्रोलिंग और टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग होता है। भारत और राजस्थान भी इनसे सीख लेकर नीतियों और संसाधनों में सुधार कर सकते हैं।

समाधान की राह

इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार – सुरक्षित सड़कें, साइनबोर्ड, स्पीड ब्रेकर। ट्रैफिक अनुशासन – कड़े कानून और जागरूक नागरिक। तकनीकी उपयोग – ड्रोन, कैमरे और ऑटोमैटिक फाइन सिस्टम। स्वास्थ्य सेवाएं – ट्रॉमा सेंटर और समय पर एम्बुलेंस। शिक्षा और जागरूकता – बच्चों और युवाओं को सड़क सुरक्षा की शिक्षा। सामाजिक सहयोग – दुर्घटना पीड़ित की मदद और 'गुड समैरिटन' कानून का पालन। राजस्थान में हर 44 मिनट में किसी की मौत सड़क हादसे में होना केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक समाज के संवेदनहीन होते जाने की तस्वीर है। सड़क सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस का काम नहीं है, बल्कि हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। सड़कें तभी सुरक्षित होंगी जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और आमजन अपनी भूमिका समझेगा। जागरूकता, अनुशासन और सहयोग के बिना हादसों को रोका नहीं जा सकता। हमें यह तय करना होगा कि हम गिलास को आधा भरा देखें और उम्मीद के साथ सड़क सुरक्षा की दिशा में मिलकर कदम बढ़ाएं। तभी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित सड़कों पर सफर कर पाएंगी।

सबक: क्या हमारे घर-फ्लैट सचमुच सुरक्षित हैं?

– सुरक्षा की अनदेखी और चेतावनी

राजस्थान के कोटा से हाल ही में आई एक दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक फ्लैट में लगी आग के चलते दो छोटे बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। यह घटना केवल कोटा की त्रासदी नहीं है, बल्कि उन सभी महानगरों और शहरों के लिए चेतावनी है, जहां ऊंची-ऊंची इमारतों में हजारों परिवार रहते हैं। सवाल उठता है कि क्या हमारे घर और फ्लैट सचमुच सुरक्षित हैं? क्या आधुनिक सुविधाओं और चमक-दमक के पीछे हमारी सुरक्षा खतरे में तो नहीं पड़ रही है?

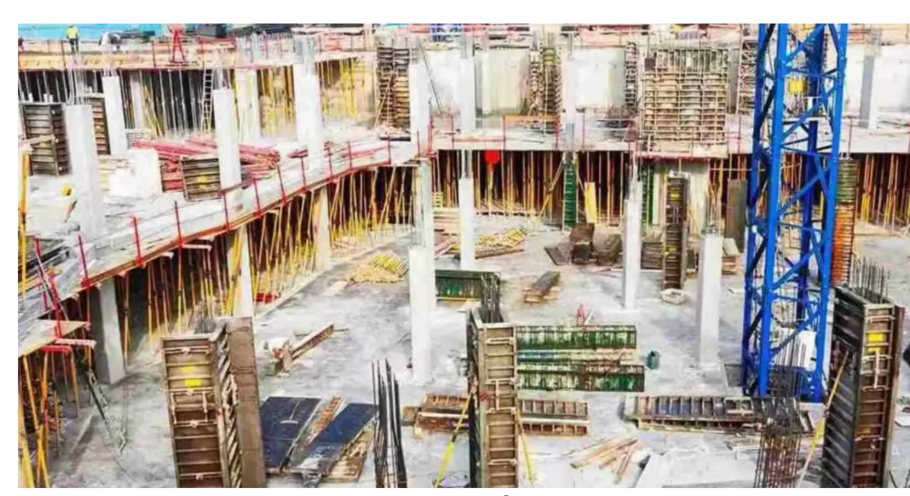

फ्लैट: मजबूरी और सुविधा

आज के समय में शहरों में फ्लैट लेना या वहां रहना केवल एक विकल्प नहीं रहा, बल्कि कई लोगों के लिए मजबूरी बन चुका है। तेजी से बढ़ती आबादी और सीमित होती जमीन के चलते ऊंची-ऊंची इमारतों का चलन बढ़ा है। फ्लैट हमें आधुनिक जीवनशैली और सुविधाजनक वातावरण का वादा देते हैं। पार्किंग, सीसीटीवी, लिफ्ट, जिम, स्विमिंग पूल जैसी चीजें इन फ्लैटों को आकर्षक बनाती हैं। लेकिन इन सब सुविधाओं के बावजूद सुरक्षा की बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। लोग सोचते हैं कि ऊंची बिल्डिंग, चमकदार लिफ्ट और सजावटी लॉबी का मतलब है कि उनका घर सुरक्षित है। हकीकत इससे बहुत अलग है।

घटनाएं जो चेताती हैं

कोटा की घटना कोई पहली दुर्घटना नहीं है। देशभर में ऐसी घटनाओं की लंबी लिस्ट है। मुंडका, दिल्ली (2022): दिल्ली के मुंडका में एक इमारत में लगी आग ने दर्जनों लोगों की जान ले ली। लोग समय पर बाहर नहीं निकल पाए और दम घुटने से उनकी मौत हुई। कमला मिल्स, मुंबई (2017): मुंबई के कमला मिल्स परिसर में देर रात आग लगने से कई लोगों की मौत धुएं के कारण हुई। इन घटनाओं में एक समान बात देखने को मिली – बिल्डर्स ने फ्लैटों को आकर्षक बनाने पर ध्यान दिया, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर ध्यान नहीं दिया। नक्शों में सुरक्षा मानक पूरे दिखा दिए गए, लेकिन जमीन पर वास्तविकता कुछ और थी।

सुरक्षा के पहलू जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है

फायर सेफ्टी: अधिकतर बिल्डिंगों में आग लगने की स्थिति में पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट, फायर डोर, फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं होते। कई बार लिफ्टें भी आग लगने पर काम नहीं करतीं।

बिल्डिंग मैटेरियल: कुछ फ्लैटों में उपयोग किए जाने वाले मैटेरियल सस्ते और जल्दी ज्वलनशील होते हैं। लकड़ी, प्लास्टिक और पुराने फर्नीचर आग फैलने में सहायक बन सकते हैं।

आपातकालीन योजना का अभाव: ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता होता कि आग लगने या किसी अन्य आपात स्थिति में क्या करना है। फ्लैट सोसाइटी में आपातकालीन ड्रिल, निर्देश और ट्रेनिंग बहुत कम होती है।

बिल्डर की जिम्मेदारी: बिल्डर अक्सर सिर्फ आकर्षक डिज़ाइन और मार्केटिंग पर ध्यान देते हैं। सुरक्षा उपायों की नियमित जांच और उनका पालन केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है।

सरकार और नियमों की भूमिका

देश में फायर सेफ्टी और बिल्डिंग सुरक्षा के नियम तो हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन बहुत कमजोर है। बिल्डिंग को बनाने से पहले नक्शा पास करवाना होता है, जिसमें सुरक्षा मानकों का हवाला दिया जाता है। निर्माण के दौरान निरीक्षण भी किया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार और अनियमितता के कारण कई बार नियमों का पालन नहीं होता। लैंड और बिल्डिंग को लेकर पारदर्शिता की कमी के कारण सुरक्षा के मामलों में जांच करना मुश्किल हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि जब आपातकाल आता है, तो घर में रहने वाले लोग असुरक्षित महसूस करते हैं।

लोगों की जागरूकता की कमी

सिर्फ बिल्डर या सरकार ही जिम्मेदार नहीं हैं। कई बार लोग भी सुरक्षा के मामलों में लापरवाह रहते हैं। आग बुझाने की यंत्रणा या फायर एक्जिट की जांच नहीं करते। बच्चों और बुजुर्गों को आपातकालीन योजना के बारे में नहीं बताते। धुएं या आग की स्थिति में लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, जो जानलेवा हो सकता है। अगर लोग थोड़ी सी जागरूकता दिखाएं और नियमित ड्रिल करें, तो कई जानें बच सकती हैं।

तकनीकी उपाय और सुरक्षा समाधान

आज के समय में तकनीकी उपायों से फ्लैटों को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है।

स्मार्ट फायर अलार्म और डिटेक्टर: ऐसे अलार्म सिस्टम जो धुएं या आग के पहले संकेत पर अलर्ट भेजते हैं, लोगों को जल्दी बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं।

स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर हाइड्रेंट: आग फैलने पर तुरंत काम करने वाले स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट सिस्टम जान बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

सुरक्षा प्रशिक्षण और ड्रिल: फ्लैट सोसाइटी में हर छह महीने में आपातकालीन ड्रिल करना जरूरी है। लोगों को यह बताना कि आग लगने पर कहाँ जाना है, कितने समय में बाहर निकलना है, बेहद महत्वपूर्ण है।

सुरक्षा उपकरण और बचाव मार्ग: फ्लैटों में फायर डोर, इमरजेंसी लाइटिंग और बचाव मार्ग हमेशा साफ और खुला होना चाहिए।

नियमित निरीक्षण: सरकारी अधिकारियों द्वारा फायर सेफ्टी निरीक्षण को नियमित और कड़ाई से लागू करना चाहिए।

शिक्षा और जागरूकता

सुरक्षा केवल उपकरणों और नियमों से नहीं आती। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता भी जरूरी है। स्कूलों और कॉलेजों में आग सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सोसाइटी स्तर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षा वर्कशॉप आयोजित करनी चाहिए। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए।

हम सभी की जिम्मेदारी

फ्लैट में रहने वाले लोग खुद भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। आग बुझाने वाले यंत्र और उपकरणों की जांच करें। बच्चों को इमरजेंसी प्लान बताएं। फ्लैट सोसाइटी के नियमों में सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान दें। सरकार, बिल्डर और आम जनता – तीनों मिलकर ही सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। कोटा की घटना ने हमें यह सख्त सबक दिया कि सुरक्षा केवल सौंदर्य और सुविधाओं के पीछे छिपी नहीं हो सकती। आधुनिकता और विकास के लिए चमक-दमक जरूरी है, लेकिन वह तब तक अधूरी है जब तक सुरक्षा की नींव मजबूत नहीं होती। हमारे घर, हमारे फ्लैट – हमारे परिवारों की जिंदगी की गारंटी नहीं हैं, अगर सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया तो। यही कारण है कि बिल्डर, सरकार और नागरिक – तीनों को मिलकर सुरक्षा की जिम्मेदारी समझनी होगी।

भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहरों का हो रहा समग्र विकास

- राजस्थान बन रहा नगरीय विकास की नई पहचान

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में नगरीय बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिली है। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आरयूआईडीपी परियोजनाओं के माध्यम से सीवरेज, जलप्रदाय, ड्रेनेज एवं शहरी सौन्दर्यीकरण के कार्यों को अभूतपूर्व विस्तार मिला है। आरयूआईडीपी के अन्तर्गत एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित शहरी क्षेत्रों में आधारभूत विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें एशियन विकास बैंक की ऋण राशि 70 प्रतिशत तथा राज्यांश 30 प्रतिशत है। इन परियोजनाओं ने न केवल शहरों की स्वच्छता और जीवन-स्तर को उन्नत किया है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी राज्य को नई पहचान दी है।

शहरी स्वच्छता और जल आपूर्ति का ढ़ांचा हो रहा सुदृढ़-
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण ट्रेंच-1 के अंतर्गत 3 हजार 76.63 करोड़ रुपये की लागत से 14 शहरों में सीवरेज एवं जलप्रदाय कार्य तथा 12 शहरों में फीकल स्लज एंड सैप्टेज मैनेजमेंट (एफएसएसएम) के कार्य कराए जा रहे हैं। इनमें से अब तक 6 शहर लक्ष्मणगढ़ (जलप्रदाय), फतेहपुर, प्रतापगढ़, डीडवाना, मकराना (सीवरेज) तथा मंडावा (सीवरेज एवं जलप्रदाय) में कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष 8 शहर सिरोही,

आबूरोड, सरदारशहर, बांसवाड़ा, खेतड़ी, कुचामन (सीवरेज एवं जलप्रदाय) एवं रतनगढ़, लाडनूं (सीवरेज) में कार्य प्रगतिरत हैं। इसी प्रकार, 12 शहरों में चल रहे एफएसएसएम (फीकल स्लज सेप्टिक मैनेजमेंट) कार्यों में से बांदीकुई, दौसा, जोबनेर और नीमकाथाना में कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा शेष 8 शहरों में कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। सितंबर 2025 तक परियोजना पर 2 हजार 302 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। इन कार्यों से लगभग 18 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

समग्र शहरी विकास का हो रहा विस्तार-
आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण ट्रेंच-2 के अंतर्गत 2 हजार 450 करोड़ रुपये की लागत से 16 शहरों में सीवरेज, जलप्रदाय, ड्रेनेज एवं शहरी सौन्दर्यीकरण कार्य प्रगति पर हैं। इनमें नोखा, बूंदी, डूंगरपुर, बालोतरा व सागवाड़ा में सीवरेज व जलप्रदाय कार्य, निंबाहेड़ा व नाथद्वारा में जलप्रदाय कार्य, जोधपुर, बाड़मेर व भरतपुर में सीवरेज कार्य; जोधपुर, नवलगढ़, रतनगढ़, बूंदी व भवानीमंडी में ड्रेनेज कार्य एवं भरतपुर, सागवाड़ा, पुष्कर व जैसलमेर में शहरी सौन्दर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। इस परियोजना के अंतर्गत अब तक 1 हजार 995 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं तथा सितंबर 2025 तक 984 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। इन कार्यों से लगभग 31 लाख लोग सीधे लाभान्वित होंगे।

सीवरेज, जलप्रदाय और स्वच्छता के क्षेत्र में मील का पत्थर-
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर एवं झालावाड़-झालरापाटन में 602 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज के तीन बड़े कार्य पूर्ण किए गए हैं, जिनसे हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिला है। उल्लेखनीय है की आरयूआईडीपी तृतीय चरण में 3 हजार 930.45 करोड रुपये से पाली, झुन्झुनु, टोंक में सीवरेज एवं जलप्रदाय कार्य, उदयपुर, माउंट आबू, बीकानेर, कोटा, सवाईमाधोपुर, झालावाड़-झालरापाटन एवं भीलवाडा मे सीवरेज कार्य एवं बांसवाडा मे ड्रेनेज कार्य पूर्ण किये जा चुके है। वहीं श्रीगंगानगर में सीवरेज एवं जलप्रदाय कार्य कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने "स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध शहरों" के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए नगरीय विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। सीवरेज, जलप्रदाय, ड्रेनेज, और एफएसएसएम जैसी परियोजनाएं न केवल शहरों की स्वच्छता और पर्यावरण को सुधार रही हैं बल्कि जनजीवन को भी स्वस्थ, सुविधाजनक और सम्मानजनक बना रही हैं। यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी नीतियों और सुशासन की प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि राजस्थान अब शहरी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

जीएसटी दरों में कमी का निर्णय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। प्रदेश के पंचायती राज एवं आपदा प्रबंधन राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जीएसटी दरों को कम करने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। देवासी सिरोही जिले में शनिवार को उद्योग संघ केसरपुरा शिवगंज की ओर से माताजी मंदिर परिसर में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद किसान केसरी लुंबाराम चौधरी ने की। राज्यमत्री देवासी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने भाषण में जीएसटी दरों में कमी की ऐतिहासिक घोषणा कर पूरे देश को एक सौगात दी है। इसके क्रियान्वयन में केंद्रीय वित्त मंत्री की सक्रिय भूमिका ने आमजन, व्यापारियों एवं उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केवल करों का बोझ घटाने वाला कदम नहीं है, बल्कि व्यापार को बढ़ावा देने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाला भी है। छोटे व्यापारी, उद्यमी और उद्योगपति सभी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नई आर्थिक ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है और यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने उद्योग संघ का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस निर्णय का पूरा लाभ प्रदेश की जनता तक पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी लागू कर न केवल व्यापारियों,उद्यमियों व आम नागरिकों को राहत दी हैं। अब जीएसटी की दरों में कमी होने से आमजन सहित व्यापारियों के लिए भी सोने पे सुहागा साबित होगा। उन्होंने उद्यमियों को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तैयार रहने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम को जीएसटी उपायुक्त महिपाल देवड़ा ने जीएसटी के संबंध में उद्यमियों को आवश्यक जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया। उद्योग संघ अध्यक्ष दिनेश बिंदल ने राज्यमंत्री देवासी के प्रयासों से रीको क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम को जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सहीराम विश्नोई व ताराराम कुमावत ने भी संबोधित किया। मंच का संचालन उद्योग संघ के महेंद्र रावल ने किया। इससे पूर्व अतिथियों का उद्योग संघ की ओर से साफा एवं पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्वदेशी अपनाने का लिया संकल्प

जयपुर/दिल्ली (रॉयल पत्रिका)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संकल्प लेते हुए कहा कि वे अपने दैनिक जीवन में अधिकतम स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे और देशवासियों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए संकल्प लिया कि "मैं, मदन राठौड़, भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूँ कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूँगा तथा आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी विकल्पों को अपनाऊँगा। मैं घर, कार्यस्थल और समाज में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूँगा तथा युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करूँगा, ताकि नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुँच सके। मैं अपने पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूँगा तथा पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी एवं प्रकृति-अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा तथा भारत के पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहित करूँगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का यह संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो देश की आर्थिक मजबूती, सांस्कृतिक गौरव और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देगा। राठौड़ ने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि वे भी इस मुहिम से जुड़ें और स्वदेशी अपनाकर राष्ट्रनिर्माण में सहभागी बनें।

विधायक मनीष यादव ने जताया विरोध

-राजस्व गाँवों को JDA में शामिल करना आमजन के साथ अन्याय

मनोहरपूर (रॉयल पत्रिका)। क्षेत्रीय विधायक मनीष यादव ने अपने x पर पोस्ट करते हुए विधानसभा क्षेत्र के राजस्व गाँवों को जबरन जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के परिधीय क्षेत्र में शामिल करने के फैसले का कड़ा विरोध जताते हुए इसे क्षेत्र की जनता के साथ बड़ा अन्याय बताया है। विधायक यादव ने कहा कि उन्होंने कई बार विधानसभा में प्रश्न, कटौती प्रस्ताव, पत्राचार और मंचों के माध्यम से सरकार को आमजन, किसानों, मजदूरों व व्यापारी वर्ग की पीड़ा से अवगत कराया, लेकिन सरकार ने जनभावनाओं की अनदेखी करते हुए तानाशाही रवैया अपनाकर यह फैसला लिया। यादव ने कहा कि विधानसभा के चतुर्थ सत्र में प्रश्नकाल के दौरान माननीय मंत्री द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यास की कार्ययोजनाएँ स्थानीय विधायक की राय से तैयार होंगी। इसके लिए 10 सितम्बर 2025 को निर्देश भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद JDA ने आदेशों की अवहेलना करते हुए शाहपुरा क्षेत्र के गाँवों को बिना राय शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आमजन, किसान, मज़दूर व व्यापारीं वर्ग को छोटे-छोटे कार्यों के लिए जयपुर जाना पड़ेगा। किसानों को भूमि संबंधी कार्य जैसे नामांतरण, अनुमति आदि के लिए JDA कार्यालयों के चक्कर काटने होंगे। वहीं स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी और विकास कार्य ठप पड़ जाएंगे।
यादव ने कहा कि JDA अपने मौजूदा क्षेत्र में ही सड़क, पानी, सीवर और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने में असफल है। ऐसे में शाहपुरा के गाँवों को JDA में शामिल करना केवल ग्रामीणों पर अतिरिक्त बोझ डालना है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि क्षेत्र की जनता की संवेदनाओं का सम्मान करते हुए गाँवों को तुरंत JDA से बाहर किया जाए। यह लड़ाई आमजन की सुविधा और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए है।

62वीं अखिल भारतीय रेलवे ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप 2025-26 संपन्न

-15 किलोमीटर स्ट्रेच रेस में उत्तर पश्चिम रेलवे के मुकेश कुमार कस्वां को मिला रजत पदक

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के तत्वाधान में उत्तर पश्चिम रेलवे स्पोर्ट्स एशोसियेशन द्वारा साइकिलिंग वेलोड्रोम, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में 2 से 4 अक्टूबर 2025 तक आयोजित 62वीं अखिल भारतीय रेलवे ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप में 08 टीमों के लगभग 70 साइक्लिस्टो ने पूर्ण उत्साह एवं ताक़त के साथ प्रदर्शन किया हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार इस चैंपियनशिप में कुल 8 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई, जिनमें सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट का पुरस्कार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रोनाल्डो सिंह को दिया गया। तथा 15 किलोमीटर स्ट्रेच रेस में उत्तर रेलवे के नमन कपिल, 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रोनाल्डो सिंह, 4 किलोमीटर इंडिविजुअल परस्यूट में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मंजीत कुमार, स्प्रिंट में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के इसोव, 20 किलोमीटर पॉइंट रेस में उत्तर रेलवे के विश्वजीत सिंह, केरीन रेस में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रोनाल्डो सिंह, टीम स्प्रिंट में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को एवं 4 किलोमीटर टीम परश्यूट में दक्षिण पश्चिम रेलवे स्वर्ण पदक विजेता रहे। समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक, अमिताभ के द्वारा प्रतिस्पर्धाओं में विजेता रहे खिलाड़ियों एवं टीमों को प्रशस्ति पत्र, पदक व नकद पुरस्कार प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि साइक्लिंग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानसिक दृढ़ता और साहस का भी प्रतीक है। आप सभी ने अपने क्षेत्र में

अद्वितीय प्रदर्शन किया है। मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने खेल के माध्यम से न केवल भारतीय रेलवे का बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगे। महाप्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे ने 62वीं अखिल भारतीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के सफल आयोजन हेतु उत्तर पश्चिम रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। चैंपियनशिप के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे के अपर महाप्रबंधक अशोक माहेश्वरी, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर शिवेंद्र मोहन, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ निर्माण राजीव श्रीवास्तव, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉ. के. कृष्ण कुमार, उप महाप्रबंधक शशांक, उत्तर पश्चिम रेलवे स्पोर्ट्स एशोसियेशन के सचिव एवं सचिव महाप्रबंधक अनुज तायल, विभागाध्यक्ष, अधिकारीगण, रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर प्रवीण व ओएसडी स्पोर्ट्स जितेंद्र कुमार सहित प्रतिभागी खिलाड़ी एवं आयोजन समिति के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

सुभाष जोशी बने जिला मीडिया प्रभारी

शाहपुरा/मनोहरपुर (रॉयल पत्रिका)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जयपुर देहात उत्तर की टीम को मजबूत करते हुए एक अहम फैसला किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप, सुभाष जोशी को जयपुर देहात उत्तर का नया जिला मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया है। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति भाजपा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में की गई है। इस आदेश का पालन करते हुए, जयपुर देहात उत्तर के जिलाध्यक्ष सुरेश बादलीवाल ने शनिवार को यहाँ आधिकारिक तौर पर जोशी की नियुक्ति की घोषणा की। माना जा रहा है कि इस रणनीतिक नियुक्ति के जरिए पार्टी जयपुर देहात क्षेत्र में अपनी मीडिया उपस्थिति और संचार रणनीति को और अधिक मजबूत व प्रभावी

बनाना चाहती है। वही जोशी के कंधों पर अब क्षेत्र में पार्टी के एजेंडे और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

कार्यालय नगरपालिका मनोहरपुर जिला जयपुर-ग्रामीण
E-mail: npmanoharpur@rajasthan.gov.in
क्रमांक :- न.पा.मनो./भूमि/2025-26/1901 दिनांक :- 04-10-2025
प्रारूप 10 [नियम 6(7) देखिये]
लोक सूचना

आवेदनकर्ता 1. श्री रमेश चंद रैगर पुत्र श्री सुवा लाल रैगर, 2. श्रीमती शारदा देवी पत्नि श्री रमेश चंद, निवासी खोराबीसल, तह. आमेर, जयपुर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन (आवासीय) उपयोग हेतु ऐसी भूमि अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात्

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्र	प्रयोजनार्थ
तह. - शाहपुरा जिला – जयपुर	शिवपुरी	8837/7465 7522, 7522/8609, 7524, 7525/2, 7525/1, 7527, 7528	800 वर्गमीटर 13700 वर्गमीटर	आवासीय आवासीय

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1956 की धारा 63 के अधिनियम पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर किसी कार्यालय दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थन दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपरोक्त वर्णित समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को कोई आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निस्तारण किया जाएगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 04.10.2025 को जारी की गई है।

प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका,मनोहरपुर

8 अक्टूबर तक विद्यार्थी कर सकेंगे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का निशुल्क भ्रमण

- वन्यजीव सप्ताह के तहत फ्री विजिट बनी स्टूडेंट्स के लिए आकर्षण केन्द्र

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। वन्यजीवों में रूची रखने वाले विद्यार्थियों के लिए 71वें विश्व वन्यजीव सप्ताह सौगात साबित हो रहा है। सप्ताह के तहत विद्यार्थी 8 अक्टूबर तक विद्यार्थी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का निशुल्क भ्रमण कर सकते हैं। नाहरगढ़ जैविक उद्यान के सहायक वन संरक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पार्क के निशुल्क भ्रमण को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार को 2,000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने पार्क का निशुल्क भ्रमण किया और वन्यजीवों की चहलकदमी एवं अठखेलियां देखकर रोमांचित हुए। उन्होंने बताया कि सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर डॉ. टी. मोहनराज के पर्यवेक्षण एवं उपवन संरक्षक (वन्यजीव) चिड़ियाघर जयपुर विजयपाल सिंह के निर्देशन में वन विभाग की ओर से विद्यार्थियों को जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के महत्व से अवगत कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। भ्रमण के दौरान विशेषज्ञ छात्रों को विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों, उनके प्राकृतिक व्यवहार और संरक्षण से जुड़ी रोचक जानकारियाँ साझा कर रहे हैं। इस पहल से बच्चों में पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीवों के प्रति जिज्ञासा और संवेदनशीलता

बढ़ रही है।
सहायक वन संरक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि शनिवार को एम.एन.आई.टी. परिसर में उपवन संरक्षक (वन्यजीव) विजयपाल सिंह के मुख्य आतिथ्य में "मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व" विषय पर जागरूकता परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त उपवन संरक्षक देवेंद्र भारद्वाज, प्रो. वीरेन्द्र सारण, वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अरविन्द माथुर, क्षेत्रीय वन अधिकारी (जयपुर प्रादेशिक) जितेन्द्र सिंह शेखावत तथा सतीश चन्द्र सहित अनेक विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए।
उन्होंने बताया कि परिचर्चा के पश्चात एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें छात्र-छात्राओं को यह बताया गया कि यदि आसपास वन्यजीव दिखाई दें तो किस प्रकार की सावधानियां बरती जानी चाहिए। वन्यजीव सप्ताह के तहत प्रतिदिन विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, निबंध लेखन, क्विज़ और जागरूकता सत्र जैसी विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को छात्र-छात्राओं के बीच चित्र पहचान प्रतियोगिता एवं लघु निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।
सहायक वन संरक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस अवसर पर कल्पतक प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल जयपुर की ओर से सर्प मित्र रवि मीणा, छात्र जितेन्द्र सिंह शेखावत (रेंजर, जयपुर प्रादेशिक), कृष्ण कुमार मीणा (सहायक वनपाल), राजाराम मीणा (सहायक वनपाल), सतीश चन्द्र एवं रोहित गंगवाल को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही, उन्होंने बताया कि 71वें विश्व वन्यजीव सप्ताह के तहत आयोजित हो रही विभिन्न गतिविधियां वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

शहरी सेवा शिविर किशनपोल के कैंप में 2400 से अधिक लोगों की समस्याओं का हुआ त्वरित निस्तारण

जयपुर। शहरी सेवा शिविर के तहत शनिवार को किशनपोल जोन के वार्ड 55, 56, 63 और 67 के निवासियों के लिए कैंप लगाया गया। पावर हाउस रोड स्थित झूलेलाल पार्क में लगाए गए कैंप में 2474 लोगों से अधिक लोगों ने आवेदन किए, जिनमें 2391 लोगों की समस्याओं के निस्तारण मौके पर ही किए गए। इस दौरान 80 से अधिक जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र बनाए गए। वहीं राशन कार्ड चालू करने के 47 प्रकरण निस्तारित किए गए। इसके अलावा तीन ट्रेड लाइसेंस , सीवर की 34 शिकायतों, स्ट्रीट लाइट की 18 शिकायत का निस्तारण और पीएम स्वनिधि योजना में 16 लोगों को लाभ दिया। वहीं, सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था, पेंशन संबंधी कार्य, चिकित्सा विभाग, समेकित बाल विकास विभाग, बिजली पानी विभाग की समस्याओं को भी मौके पर ही निस्तारण कराया गया। इस दौरान निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी मौके जन सुनवाई की। आयुक्त ने शिविर का किया निरीक्षण, 74 वर्षीय महिला का बना जन्म प्रमाण पत्र

वहीं, हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने शहरी सेवा शिविर में चले रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जोन उपायुक्त, मुख्यालय के सभी शाखाओं के प्रभारी और इंजीनियरिंग विंग के अधिकारी मौजूद रहे। निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से चल रहे कैंप में आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना प्रमुख लक्ष्य रखा जाएं। कैंप आ रहे लोगों को सही जानकारी दी जाएं, अगर किसी कारण वश तुरंत निस्तारण नहीं किया जा रहा है तो संबंधित आवेदक को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएं। इस दौरान एक 74 वर्षीय महिला का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया।

शहरी सेवा शिविर में आमजन को मिल रही ये सुविधाएं:-
हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल ने बताया कि शिविर में निगम से संबंधित कार्य किए जा रहे है। जिसके अंतर्गत सफाई कार्य, स्ट्रीट लाइट रिपेयर, फेरोकवर रिपेयर, ब्लैक स्पॉट सही कराना, सीवरेज कनेक्शन, कार्यालय में पेंडिंग पत्रावलियों का निस्तारण, विभिन्न प्रकार के पट्टा संबंधी कार्य, ट्रेड लाइसेंस, फायर एनओसी, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन, उप विभाजन एकीकरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, पीएम - सीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एसबीएम 2.0 के तहत घरेलू शौचालय निर्माण जैसे कार्यों के आवेदन लिए जाएंगे और कैंप में ही निस्तारण प्रक्रिया जाएगी।

आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल — केसंस फार्मा की फैक्ट्री पर धरना

-कंपनी पर ताला लगाने और सभी दवाओं पर तुरंत बैन की मांग

जयपुर। राजस्थान में केसंस फार्मा द्वारा निर्मित खांसी की सिरप से अब तक तीन मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने इसे प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही और दोषी कंपनियों को संरक्षण देने का गंभीर उदाहरण बताया है। इसी मुद्दे पर शनिवार को सुबह 11:30 बजे से जयपुर के सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित केसंस फार्मा फैक्ट्री के बाहर "हल्ला बोल प्रदर्शन" किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री पर प्रतीकात्मक ताला लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर फैक्ट्री को घेर लिया। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया और शांतिपूर्ण धरना रोक दिया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने केसंस फार्मा की सभी दवाओं पर तत्काल बैन लगाने और दिवंगत तीन मासूम बच्चों सहित उन दस से अधिक बच्चों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की, जो इस जहरीली सिरप की चपेट में आकर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान आशुतोष रांका, दीपक बलियान, अमित दाधीच, सैयद राशिद हसन, अमित वशिष्ठ, रेखा शर्मा, सुनील अग्रवाल, विनीत शर्मा, धीरज जैन, विशाल सैनी, वीरेंद्र चौधरी, राजपाल फोगावत, फिरोज कुरैशी, मोहसिन खान, आदित्य कुशवाह सहित बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता शामिल हुए।

आवश्यक नम्बर

रॉयल पत्रिका

बिजली फॉल्ट के लिए	
टोल फ्री नंबर	18001806507
वॉट्सएप नंबर	9414037085
कस्टमर केयर	2203000
आईवीआरएस	1912
कचरा गाड़ी के लिए	
ग्रेटर	2747400
सीवरेज लीकेज	2607500
हेरिटेज	2607500
टोल फ्री नंबर	14420
पुलिस की मदद के लिए	
साइबर क्राइम	1930/2360094
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
महिला हेल्पलाइन	1090
मुख्यमंत्री पोर्टल	181

पानी के लिए	
जलदाय कार्यालय	2706624
फायर ब्रिगेड	2747400
मेडिकल इमरजेंसी के लिए	
एंबुलेंस	102/108
एसएमएस इमरजेंसी	2518333
महिला चिकित्सालय	22610616
जनाना हॉस्पिटल	22378721
SDMH	22574189
SMS ब्लड बैंक	22518222
कल्याण ब्लड बैंक	22721771
घायल पशुओं के लिए	
नगर निगम	2747400
बर्ड बाइक	9887345580
हेल्प इन सफरिंग	8107299711
जनमंच ट्रस्ट	7230055800
पशु चिकित्सालय	2747400

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत प्रस्तावों पर जिला कलक्टर ने की चर्चा

बारां (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की अध्यक्षता में शुक्रवार को मिनी सचिवालय सभागार में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत प्राप्त प्रस्तावों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ही सभी ब्लॉक नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। जिला कलक्टर ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जिले के चिन्हित 277 गांवों से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि गांव स्तर पर लागू किए जाने वाले प्रस्तावों पर संबंधित विभागों की गाइडलाइन और नियमों की समीक्षा की जा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो नियमों में बदलाव के संबंध में भी विचार किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान के तहत प्राप्त विलेज विजन प्लान का गहन अध्ययन करें और विभागवार चेकलिस्ट तैयार करें, ताकि गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर एडीएम भंवर लाल जनागल, एडीएम जबर सिंह, एएसपी राजेश चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सीएमएचओ ने डायग्नोस्टिक सेन्टर व लैब का किया औचक निरीक्षण

-मौके पर ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के तहत पंजीकरण करने के लिए किया निर्देशित

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। जिले मे संचालित डायग्नोस्टिक सेंटर्स व लैब्स का औचक निरीक्षण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जैमिनी द्वारा राजकीय चिकित्सालय के सामने तथा अन्य स्थानों पर स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर्स व लैब्स का औचक निरीक्षण किया गया। लैबों की जांच करने पर पाया गया कि, क्लिनिक ऐस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बिना पंजीकरण करवाये ही लैब व डायग्नोस्टिक सेन्टर्स का संचालन किया जा रहा था। जिस पर सभी को मौके पर ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के तहत पंजीकरण के आवेदन मय वांछित दस्तावेजों के तत्काल ही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित स्टॉफ, टेक्निशियन इत्यादि से डायग्नोस्टिक सेन्टर लैब संबंधित पंजीकरण प्रमाण पत्र, जांच रिपोर्टिंग, उपकरणों व सुरक्षा उपकरणों इत्यादि की जानकारी ली गई। लैब में गंदगी पाई जाने पर तुरन्त साफ सफाई के निर्देश दिये गये। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उक्त पंजीकरण करवाये जाने के लिए स्थानीय समाचार पत्री में विभाग द्वारा जनहित में सूचनाएं देकर समाचार प्रकाशित करवाया गया था जिस पर कई लैबों एवं हॉस्पिटल के आवेदन कार्यालय में भी प्राप्त हुये, जिनका नियमानुसार पंजीकरण भी किया जा चुका है और शेष पंजीकरण आवेदनों की कार्यवाही विचाराधीन चल रही है।

दुर्लभ दवा और दवा युक्त खीर का वितरण 7 अक्टूबर को

झुंझुनूं (रॉयल पत्रिका)। पिछले 45 सालों से चलती आ रही परम्परा/पद्धति को डॉ. सलाउद्दीन चोपदार फाउंडेशन बरकरार रखते हुवे इस बार भी दमा, श्वांस, एलर्जी जैसे असाध्य रोगों के ईलाज के लिए दुर्लभ दवा का वितरण 7 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से किया जायेगा.....लेकिन इस बार फाउंडेशन सिर्फ दुर्लभ दवा ही नहीं, बल्कि पोष्टिक खीर का वितरण भी करेगी। इस दौरान एक तरफ जहां विद्वान पंडितों द्वारा आयुर्वेद सिद्ध मंत्रोच्चारण किया जाएगा तो दूसरी तरफ दमा, श्वांस, एलर्जी जैसे असाध्य रोगों से पीड़ित लोग दुर्लभ दवा युक्त केसरिया व ड्राई फ्रूट्स वाली खीर का सेवन करेंगे। फाउंडेशन के संयोजक समाजसेवी एम.डी. चोपदार ने बताया कि वारिसपुरा रोड स्थित आयुर्वेद पार्क डॉ. एस.डी. चोपदार आयुष हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर दवा का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सक व अन्य विशेषज्ञों के निर्देशन में फाउंडेशन द्वारा आयुर्वेद पार्क में ही खीर बनवाई जाएगी। जिसे शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में रखा जाएगा। जिसका पौराणिक एवं आध्यात्मिक के साथ—साथ आयुर्वेदिक महत्व भी है। हर वर्ष कि तरह दुर्लभ दवा के सेवन के लिए उमड़ते रोगियों की संख्या को ध्यान में रखते हुवे इस वर्ष करीब पांच हजार लोगों को दुर्लभ दवा युक्त खीर वितरित करने का लक्ष्य लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए विशेष रूप से मिट्टी के बर्तन भी मंगवाए गए है। जिसमें खीर वितरित होगी और आपको बता दें इस दवा को लेने के लिए हर साल राजस्थान के विभिन्न जिलों के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और एमपी जैसे पड़ौसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में रोगी व इनके परिजन पहुंचते है। लेकिन इस बार फाउंडेशन ने सिर्फ दवा ही नही बल्कि दवा युक्त खीर का वितरण सम्पूर्ण आध्यात्मिक माहौल में करने का कदम उठाया है।

दिव्यांगजन के लिए ब्लॉक स्तर पर लग रहे शिविरों में बने यूडीआईडी कार्ड

-जिला कलक्टर ने दिव्यांगजनों से की अपील- नजदीकी शिविर में पहुंचकर कराएं समस्याओं का समाधान

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लॉकों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य पात्र दिव्यांग व्यक्तियों का असेसमेंट कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड तुरंत उपलब्ध कराना है। जिला कलक्टर काना राम के नवाचार और प्रयासों से जिले के ब्लॉको मे माइक्रो प्लान के अनुसार शिविर लगाए जा रहे है। शुक्रवार को ब्लॉक सीएचसी चौथ का बारवाड़ा व सीएचसी वजीरपुर मे शिविर लगा कर प्रमाण पत्र बनाये गये। पांच दिन पूर्व प्रारंभ किये गये शिविरों मे अब तक कुल 102 दिव्यांग जनों के प्रमाण पत्र बनाये जा चुके है। इस प्रकार होंगे शिविरों आयोजित :- सीएमएचओ डॉ. अनिल कुमार जैमिनी ने बताया कि 3 एवं 4 अक्टूबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौथ का बरवाड़ा एवं सीएचसी वज़ीरपुर में, 6 एवं 7 अक्टूबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलारना डूंगर व समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंडार में विशेष शिविरों का आयोजन होगा। साथ ही जिला अस्पताल सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी में प्रतिदिन विशेष शिविर आयोजित किये जाएंगे। शिविरों में हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ शामिल रहेंगे। साथ ही तकनीकी सहयोग हेतु सूचना सहायक, डीईओ तथा ब्लॉक सीएमओ द्वारा नामित कार्मिक भी तैनात रहेंगे। आशा कार्यकर्ता व एएनएम को घर-घर जाकर पात्र दिव्यांगजनों को शिविरों की सूचना देने के लिये निर्देशित किय गया है ताकि कोई भी लाभार्थी वंचित न रह जाए। जिला कलक्टर काना राम ने सभी दिव्यांग व्यक्तियों से अपील की है कि वे नजदीकी शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से दिव्यांगजन न केवल अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज प्राप्त करेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से भी सीधे जुड़ सकेंगे।

स्पोन्सर्स ने किया स्त्री शक्ति महिला समूह का सम्मान

झुंझुनूं (रॉयल पत्रिका)। स्त्री शक्ति महिला समूह की ओर से आयोजित तीन दिवसीय डांडिया—गरबा महोत्सव राविरा—2025 के सफल आयोजन पर आयोजन के स्पोन्सर्स ने स्त्री शक्ति महिला समूह का आभार जताते हुए आयोजन को शानदार और जानदार बताया है। इसी क्रम में रामेश्वरम नगर हाउसिंग सोसायटी ने आयोजन समिति का सम्मान करते हुए कहा कि ना केवल आयोजन भव्य था। बल्कि अनुशासन देखने लायक था। नियमों की पालना में सख्ती के कारण पूरा आयोजन पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ। समूह की ललित राठौड़ ने बताया कि रामेश्वरम नगर हाउसिंग सोसायटी की ओर से लक्की ड्रॉ के जरिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटी रिया गाडिया, डबल डोर फ्रीज समुदर सिंह तथा एलईडी मनीषा को दी गई। इसके अलावा कई कैश प्राइज भी दिए गए। वहीं 21000 रूपए का द रश्मिका अवार्ड डॉ. अन्नुश्री को, 11 हजार रूपए का ईनाम राविरा विनर दीपिका सैनी को तथा 5100 रूपए के डांसिंग डॉल प्राइज भव्या व ऋतिका को दिया गया। राठौड़ ने बताया कि नियमों की सख्ती से पालना करते हुए और पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ ही सभी पुरस्कार दिए गए। जिसकी सभी ने सराहना की। इस मौके पर शिक्षा के लिए एक बच्ची को गोद लेने, सिलाई, पिकू मशीन व अल्ट्रा मॉर्डन सिलाई मशीन का वितरण जैसे सामाजिक सरोकार के कार्यों की सराहना की। ललित राठौड़ ने बताया कि आयोजन की व्यवस्तता के बावजूद स्त्री शक्ति महिला समूह की महिलाओं ने रक्तदान करके एक बच्चे की जान भी बचाई। एक डेंगू के सीरियस पेसेंट को 10 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। जिसे पूरा किया। डॉ. शालू टीबड़ा ने बताया कि अनंत सुखरामजी ट्रस्ट की झुंझुनूं ब्रांच के तत्वावधान में भी सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाते है। ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में भी स्त्री शक्ति महिला समूह की सदस्यों ने हिस्सा लिया था। वहीं स्त्री शक्ति समूह के बालिका शिक्षा के संकल्प को भी ट्रस्ट के सहयोग से पूरा किया जा रहा है। समूह की डॉ. मीना शेखावत, रविता चौधरी तथा सुमन मील ने बताया कि स्त्री शक्ति महिला समूह आगे भी इसी तरह के सामाजिक सरोकारों को निभाता रहेगा। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देगा।

ग्रामीण सेवा शिविर द्वारा 30 वर्षो से लंबित बंटवारे का निस्तारण

डूंगरपुर (रॉयल पत्रिका)। 03 अक्टूबर 2025 को ग्रामीण सेवा शिविर का कैंप ग्राम पचांयत गैड में आयोजित किया गया। कैंप के द्वारा 30 वर्ष से अधिक लंबित बटवारा के प्रकरण के लिए प्रयासरत थे। उपखडं अधिकारी शाहीन अजंमु ने तत्परता दिखाते हुए तहसीलदार बिछीवाड़ा को आदेश दिया। मौके पर नायब तहसीलदार अनिल पंड्या द्वारा गिरदावर व पटवारी से बटवारा तैयार करवाकर मौके पर ही बटवारा किया गया। कैंप में अजय जोशी एवं विभिन्न वि भाग के अधिकारी कर्मचर्मारी उपस्थित रहे।

राजस्थान राज्य बैडमिंटन चैम्पियनशिप का शुभारम्भ 05 अक्टूबर से

-राज्य भर से 700 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम

झुंझुनूं (रॉयल पत्रिका)। यॉनेक्स सनराईज राजस्थान स्टेट बैडमिंटन 2025 सब जूनियर अंडर 11 एवं 13 आयु वर्ग बालक - बालिका मैन ड्रा चैम्पियनशिप का शुभारम्भ जिला बैडमिंटन संघ की ओर से वैन्यू पार्टनर झुंझुनूं एकेडमी विज़्डम सिटी में 05 अक्टूबर को प्रातः 10: 15 बजे होगा। जिसके लिए सभी खिलाड़ी,टेक्निषियन, मैच अंपायर एवं मैच रेफरी झुंझुनूं पहुंच चुके है। जानकारी देते हुए जिला बैडमिंटन संघ अध्यक्ष डॉ. दिलीप मोदी ने बताया कि झुंझुनूं एकेडमी में आयोजित होने वाली बैडमिंटन चैम्पियनशिप की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस चैम्पियनशिप में 11 एवं 13 वर्ष बालक एवं बालिका वर्ग में एकल व युगल मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में राजस्थान के सभी जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे और प्रतियोगिता के पहले दो दिन क्वालीफाइंग मुकाबले 03 अक्टूबर से हो रहे है। जिसमें 68 से अधिक खिलाड़ियों ने मैन ड्रा के लिए क्वालिफाई किया है। जिनके मुकाबले 05 से 08 अक्टूबर को खेले जायेगे तथा 300 से अधिक खिलाड़ी मैन ड्रा में अपना दमखम दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि झुंझुनूं जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा सिंघानिया यूनिवर्सिटी प्रसिडेन्ट डॉ. मनोज कुमार एवं राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन सचिव के.के शर्मा विशिष्ट अतिथि होंगे। इस चैम्पियनशिप को सिंघानिया यूनिवर्सिटी स्पोन्सर कर रही है तथा झुंझुनूं एकेडमी विज्डम सिटी वैन्यू पार्टनर है। जिला बैडमिंटन संघ सचिव मनीष कुमार ने बताया कि शेखावाटी में दूसरी बार इतने बड़े स्तर पर बैडमिंटन चैम्पियनशिप का आयोजन जिले में हो रहा है जहाँ 700 से अधिक खिलाड़ी जिले में एक साथ जुटेंगे इससे एक अच्छी प्रस्तिपर्धा देखने को मिलेगी। चैंपियनशिप प्रभारी श्याम सुन्दर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चैम्पियनशिप की सम्पूर्ण तैयारियां पूरी कर ली गई है सभी खिलाड़ियों के रहने और खाने पीने की उत्तम व्यवस्थाएं झुंझुनूं एकेडमी छात्रावास में की गई है। मैच रेफरी चन्द्र प्रकाश शर्मा और मैच कंट्रोलर विनित शर्मा की टीम ने सभी तैयारियों एवं बैडमिंटन कोर्ट का का पूर्ण जायजा एवं सभी तैयारियों का सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद कहा कि बेहतरीन तकनीकी टीम, विश्व स्तरीय बैडमिंटन कोर्ट सहित सभी व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की है जो सभी खेल मापदंडों को पूर्ण करती हैं साथ ही कहा कि झुंझुनूं जिले में इस तरह की बैडमिंटन एकेडमी का होना गौरव की बात है जहाँ नेशनल और स्टेट लेवल की चैम्पियनशिप का आयोजन होता है उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं की भूरि भूरि प्रशंसा की। इस अवसर पर बैडमिंटन संघ संरक्षक कुरड़ाराम धींवा, संघ सदस्य आकाश मोदी, स्कूल प्राचार्य डॉ. रवि शंकर शर्मा, उपप्राचार्या सरोज सिंह बैडमिंटन कोच नितेश वर्मा उपस्थित थे।

अपराधी सुधार दिवस पर किशनगढ़बास उप कारागृह में विचार गोष्ठी का आयोजन

खैरथल-तिजारा (रॉयल पत्रिका)। समाज कल्याण सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को उप कारागृह किशनगढ़बास में अपराधी सुधार दिवस के अवसर पर समाज कल्याण अधिकारी गजराज यादव की अध्यक्षता में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में बंदियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही, बंदियों को पालनहार योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। समाज कल्याण अधिकारी ने बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के निर्देश भी दिए, ताकि उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सके। इस अवसर पर जेल अधीक्षक रामेश्वर लाल, जेल प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी, तथा समाज कल्याण विभाग से नवीन यादव और सौरभ चौधरी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्तान जिंक के सबसे पुराने देबारी जिंक स्मेल्टर में महिलाओं के लिए नाईटशिफ्ट की शुरुआत

-कंपनी के सभी स्मेल्टर और चार माइंस अब महिला इंजीनियरों के साथ पूर्णकालिक रूप से संचालित

उदयपुर (रॉयल पत्रिका)। भारत की एकमात्र और दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक कंपनी, हिन्दस्तान ज़िंक लिमिटेड ने अपनी विविधता और समावेशन की यात्रा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, राजस्थान के उदयपुर स्थित भारत के सबसे पुराने जिंक स्मेल्टर, जिंक स्मेल्टर देबारी में महिला कर्मचारियों के लिए नाईटशिफ्ट की शुरुआत की है। कंपनी ने अपने प्रमुख परिचालनों में महिला कर्मचारियों के लिए पहले ही बैकशिफ्ट (दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक) और नाइटशिफ्ट (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक) शुरू कर दी है, जिनमें राजस्थान और उत्तराखंड में रामपुरा आगुचा माइन, पंतनगर मेटल प्लांट, चंदेरिया स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स, कायड़ माइन, जावर माइंस और सिंदेसर खुर्द माइन शामिल हैं। इन प्रगतिशील कदमों से हिन्दस्तान जिंक़ ने 26 प्रतिशत से अधिक का जेंडर डायवर्सिटी अनुपात हासिल किया है, जो भारत के मेटल, माइनिंग और हैवी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में सबसे अधिक में से एक है। साथ ही महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मजबूत उपाय किए गए हैं, ताकि उन्हें एक सुरक्षित कार्यस्थल मिल सके। इस उपलब्धि के बारे में हिन्दस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन, प्रिया अग्रवाल हेब्बर ने कहा कि, यह हिन्दस्तान जिंक के लिए गर्व का क्षण है और भारत के मेटल और माइनिंग सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे जिंक स्मेल्टर देबारी में महिलाओं को नाइटशिफ्ट में शामिल कर, हम न केवल बाधाओं को तोड़ रहे हैं, बल्कि समावेशन के नए मानक भी स्थापित कर रहे हैं। सच्ची प्रगति प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से भाग लेने, निडर होकर नेतृत्व करने और समान रूप से आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाने से आती है - और हम एक ऐसा कार्यस्थल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं जहाँ विविधता नवाचार और विकास को बढ़ावा देती है। अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत सुरक्षा उपायों और प्रगतिशील नीतियों के साथ, हिन्दस्तान ज़िंक पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान कार्यस्थलों को भविष्य के लिए तैयार, समावेशी वातावरण में बदलना जारी रखे हुए है। भारत की पहली महिला भूमिगत खदान प्रबंधकों की नियुक्ति से लेकर देश की पहली महिला भूमिगत खदान बचाव टीम की स्थापना तक, कंपनी की अग्रणी पहल लैंगिक समावेशन के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देबारी में स्मेल्टर संचालन की ग्रेजुएट ट्रेनी, रुबीना अगवानी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि, जिंक स्मेल्टर देबारी में नाईटशिफ्ट में काम करने वाली पहली महिलाओं में शामिल होना एक सशक्त अनुभव है। हिन्दस्तान जिंक की समावेशी संस्कृति, सुरक्षा प्रोटोकॉल और मार्गदर्शन ने मुझे सीमाओं को आगे बढ़ाने और पेशेवर रूप से आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया है। यह पहल न केवल मेरे करियर को आगे बढ़ाएगी, बल्कि मेटल और माइनिंग सेक्टर में अवसरों का लाभ उठाने के लिए अन्य महिलाओं को प्रेरित भी करेगी। हिन्दस्तान ज़िंक के लिए, विविधता और समावेशन मुख्य व्यावसायिक अनिवार्यताएं हैं। नियामकों के साथ साझेदारी में, कंपनी अवसर प्रदान कर रही है और बाधाओं के बिना भविष्य को आकार दे रही है। यह एक ऐसे कार्यस्थल की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है जहां विविधता नवाचार को बढ़ावा देती है और समावेशन विकास को गति देता है। जैसे-जैसे दुनिया धातु-प्रधान भविष्य की ओर बढ़ रही है, हिन्दस्तान जिंक एक न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व पारंपरिक रूप से कम रहा है, कंपनी धातु और खनन क्षेत्र में बढ़ते कौशल अंतर को पाटने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानती है। सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सक्रिय रूप से बढ़ाकर, कंपनी उद्योग को महिला पेशेवरों के लिए अधिक समावेशी, विविध और आकांक्षी बना रही है। हिन्दस्तान जिंक का प्रमुख अभियान, वुमेन ऑफ जिंक, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उद्योग के भविष्य को आकार देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। 2030 तक 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की मजबूत प्रतिबद्धता के साथ, कंपनी न केवल अपने कार्यबल में बदलाव ला रही है, बल्कि जिंक को ध्यान में रखते हुए धातुओं के भविष्य को पुनर्परिभाषित और नेतृत्व भी कर रही है।

हिन्दुस्तान जिंक द्वारा पशु कल्याण को बढ़ावा देकर, वर्ष 2016 से अब तक 8.7 लाख से अधिक पशु लाभान्वित

-बाघदड़ा नेचर पार्क में मगरमच्छ संरक्षण एवं इको टूरिज्म के लिए 5 करोड़ का सहयोग

उदयपुर (रॉयल पत्रिका)। दुनिया की सबसे बड़ी जिंक उत्पादक कंपनी, हिन्दस्तान जिंक देश में पशु कल्याण और जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कंपनी द्वारा पशु कल्याण स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 8.7 लाख से अधिक पशु लाभान्वित हुए है। कंपनी ने सामाजिक प्रभाव के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर एक ऐसा विजन प्रस्तुत किया है जहाँ वन्यजीव और पारिस्थितिकी तंत्र समुदायों के साथ तालमेल कर आगे बढ़ रहे है। कंपनी के दृष्टिकोण पर हिन्दस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक अरुण मिश्रा ने कहा कि, पशु कल्याण और जैव विविधता संरक्षण हमारे सस्टेनेबल एजेंडा के केंद्र में हैं। हमारे हस्तक्षेप न केवल लुप्तप्राय और स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण, बल्कि उन पशुधन के स्वास्थ्य में भी सुधार करते हैं जिन पर ग्रामीण समुदाय निर्भर हैं। ये पहलें हमारे इस विश्वास को दर्शाती हैं कि पारिस्थितिक संरक्षण और सामुदायिक समृद्धि साथ-साथ विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

बागदड़ा मगरमच्छ अभयारण्य का विकास-

इस प्रयास में एक बड़ा मील का पत्थर उदयपुर वन विभाग के साथ 5 करोड़ का एमओयू है, जिस पर बागदड़ा मगरमच्छ संरक्षण अभयारण्य एवं इको टूरिज्म को विकसित करने हेतु प्रयास किया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य क्रोकोडाइल, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित सरीसृपों में से एक हैं, के प्राकृतिक निवास स्थान को बहाल करना है। इसकी शुरुआत हाल ही में 5 हजार पौधों के साथ वनीकरण, जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण और इको-ट्रेल बनाने से हुई है, जो लोगों को जिम्मेदारी से प्रकृति का अनुभव करने की अनुमति देते हैं। स्थानीय निवासियों को सस्टेनेबल आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए सामुदायिक-नेतृत्व वाले इको-टूरिज्म की सुविधाएँ भी विकसित की जा रही हैं।

जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहल-

इसके साथ ही, हिन्दस्तान जिंक ने राजस्थान में अपनी कायड खदान में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के लिए एक पीकॉक पार्क विकसित किया है। इस पहल को कायड और रामपुरा आगुचा माइंस में लुप्तप्राय प्रजाति नर्सरी के निर्माण से बल मिला है। ये लुप्तप्राय वनस्पतियों को विकसित होने और फैलने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती हैं। जैव विविधता को और बढ़ाने के लिए, कंपनी ने कई परिचालन स्थलों पर पक्षियों के घोंसले और दाने के स्टेशन , बटरफ्लाई गार्डन और पानी के तालाब लगाए हैं। ये प्रयास ऐसे सूक्ष्म निवास स्थान बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो स्थानीय प्रजातियों को आकर्षित करते हैं और उन्हें संरक्षित करते हैं। कंपनी, वेदांता समूह की एक प्रमुख पहल द एनिमल केयर ऑर्गनाइजेशन टीएसीओ के सहयोग से, विभिन्न पशु कल्याण पहलों में भी योगदान दे रही है।

पशु स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम-

हिन्दस्तान जिंक के पशु कल्याण कार्यक्रमों ने अपने पशु कल्याण केंद्र, पशु स्वास्थ्य शिविरों, लम्पी स्किन डिजीज निवारण अभियान और रिफ्लेक्टिव कॉलर पहल के माध्यम से भी महत्वपूर्ण प्रयास किये गये है। ये कार्यक्रम स्वस्थ पशुधन सुनिश्चित करते हैं, बीमारी के खतरों को कम करते हैं और किसानों को उत्पादकता में सुधार के लिए जानकारी और संसाधन के साथ सशक्त बनाते हैं, जिससे पशु कल्याण और ग्रामीण समृद्धि के बीच सीधा संबंध बनता है। ये सभी हस्तक्षेप टास्कफोर्स ऑन नेचर-रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के तहत कंपनी की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं। अपने व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से हिन्दस्तान जिंक यह मानक स्थापित कर रही है कि औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। वन्यजीवों के संरक्षण, प्राकृतिक आवास को बहाल करके और समुदायों को सशक्त बनाकर, हिन्दस्तान जिंक भारत में जैव विविधता और जिम्मेदार खनन के लिए कॉर्पोरेट नेतृत्व के नए मानदंड स्थापित कर रही है।

गंगानगर स्थापना दिवस की पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित

-जिला कलक्टर ने दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। गंगानगर स्थापना दिवस की पूर्व तैयारियों को लेकर जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इस दौरान गंगानगर जिला स्थापना दिवस (26 अक्टूबर 2025) को समारोहपूर्वक आयोजित करने पर चर्चा करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि पर्यटन विभाग की ओर से आवश्यक कार्य योजना तैयार की जाये। इसमें जिला स्तरीय अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाये। बैठक में जिला स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि बॉर्डर टूरिज्म को विकसित करने के साथ-साथ शिवपुर हैड और नग्गी क्षेत्र में भी पर्यटन संबंधी गतिविधियां बढ़ाई जाये। इसके लिये पर्यटन विभाग के साथ-साथ जिला स्तरीय अधिकारी भी आवश्यक कार्य योजना बनाएं। सूरतगढ़ में एक शाम धोरों के नाम सांस्कृतिक संध्या के अलावा श्रीकरणपुर के नग्गी क्षेत्र में बीएसएफ के सहयोग से कार्यक्रम आयोजन पर भी चर्चा हुई। उक्त कार्यक्रमों के संबंध में सुझाव आदि लेते हुए व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये गये। बैठक में एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार, एसडीएम गंगानगर नयन गौतम, एसडीएम सूरतगढ़ भरत जयप्रकाश मीणा, एएसपी रघुवीर शर्मा, आयुक्त नगरपरिषद रविन्द्र यादव, जिला परिषद एसीईओ हरीराम चौहान, धीरज चावला, जिला पर्यटन अधिकारी पवन शर्मा, दीपक कुक्कड़, विजय कुमार, कविता सिहाग, सरोज, गिरजेश कांत शर्मा, सुरेन्द्र बिश्नोई, मनोज मोदी सहित अन्य मौजूद रहे।

जिला स्तरीय एनसीओआरडी समिति की बैठक आयोजित

-मादक पदार्थों के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करें- लोक बन्धु

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। जिला स्तरीय एनसीओआरडी समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिले में नशे की रोकथाम, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण और नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलक्टर लोक बन्धु ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जिले में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इससे पूर्व की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। बैठक में अब तक की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए पंजीकृत प्रकरणों और जब्त नशीले पदार्थों का विश्लेषण किया गया। उन्होंने कोटपा के अंतर्गत अधिकाधिक चालान की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गृह विभाग के अधिकारियों को सूचना तंत्र सुदृढ़ करने एवं संदिग्ध स्थानों एवं मार्गों पर विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को अन्य एजेंसी से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए। रेस्टोरेंट में हुक्का बार संचालित करना प्रतिबंधित है। इस पर निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती नशाग्रस्त व्यक्तियों की जानकारी ली और पुनः नशे की लत नहीं लगे इसकी जांच एवं निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही समाज में नशे के दुष्प्रभाव पर जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधि आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ड्रग एडिक्शन के प्राप्त केसेज की जानकारी लेते हुए मेडिकल स्टोर्स पर साइकोट्रॉपिक एवं शेड्यूल एच ड्रग्स की बिक्री बिना चिकित्सकीय पर्चे के नहीं होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दवाई विक्रेता द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा एवं समाज कल्याण विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष अभियान चलाकर जागरूकता लाने के निर्देश दिए।

भिवाड़ी इंडस टेक के 32वें संस्करण में मंत्री झाबर सिंह खर्रा हुए शामिल

-इंडस टेक के 32वें संस्करण में पहुंचे मंत्री झाबर सिंह खर्रा

खैरथल-तिजारा/भिवाड़ी (रॉयल पत्रिका)। इंडस टेक के 32वें संस्करण में राज्य के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन करते हुए प्रदर्शित नवीनतम तकनीको की जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन राज्य में तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उद्योगों को नई दिशा प्रदान करते हैं। राज्य नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खर्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि पिछले दशक में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की गईं, जिनके परिणामस्वरूप आज युवा विदेश जाने के बजाय अपनी ही धरती पर उद्योग स्थापित कर न केवल स्वयं के लिए बल्कि अनेकों लोगों के लिए रोजगार सृजित कर रहे हैं। मंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाला समय भारत का होगा और देश विश्व में एक विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को सशक्त करने हेतु लिए गए निर्णय, जैसे जीएसटी सरलीकरण, ने औद्योगिक क्षेत्र और आमजन दोनों को लाभान्वित किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर रोड कनेक्टिविटी से न केवल उद्योगों की उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ी है बल्कि निवेश और रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उद्योगों के विकास से न केवल युवाओं को नए अवसर मिलेंगे बल्कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक मजबूती भी आएगी। खर्रा ने कहा कि सरकार द्वारा लाई जा रही औद्योगिक नीतियां और रोजगारोन्मुख योजनाएं तभी सफल होंगी जब युवा उनमें सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे आधुनिक तकनीक और नवाचार का उपयोग कर छोटे और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ाएं, जिससे भिवाड़ी क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

समाज कल्याण सप्ताह के तहत बंदी सुधार दिवस कार्यक्रम आयोजित

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा समाज कल्याण सप्ताह के अन्तर्गत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में शुक्रवार को बंदी सुधार दिवस का कार्यक्रम केंद्रीय कारागार में आयोजित किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक वीरेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने कैदियों को मुख्यधारा में जीवन में जुड़ने का आह्वान किया। इस दौरान जेल में रहते हुए आईटीआई करने वाले तीन बंदियों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। उपनिदेशक सिंल द्वारा पैरोल इत्यादि के बारे में बताया गया। जेल अधीक्षक महावीर द्वारा धन्यवाद दिया गया जबकि विभाग की ओर से फल वितरित किये गये।

चाइल्ड हेल्पलाइन ने दी बाल विवाह की जानकारी

डूंगरपुर (रॉयल पत्रिका)। डूंगरपुर शहर में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन ने 3 अक्टूबर 2025 वार शुक्रवार को ब्लॉक डूंगरपुर ग्राम पंचायत सतीरामपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को बाल विवाह के बारे में जानकारी एवं शपथ दिलाई गई। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक कल्पित शर्मा ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक मेहुल शर्मा के निर्देशन में केश सुपरवाईजर नारायण लाल बरण्डा, महेंद्र कलाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सती रामपुर में जाकर बच्चो को बाल विवाह एवं बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में समझाते हुए कहाॅ की बाल विवाह करना एवं करवाना जुर्म है एवं बताया कि करने और करने में शामिल होने वाले जैसे रिश्तेदारों,बारातियों तथा सहयोग करने वाले- हलवाइयों, टैण्ट, शामियाना, बैण्ड बाजे, साउण्ड, फोटोग्राफर, पण्डित व अन्य के लिए सजा एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 2 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार 3 वर्ष की सजा 1 लाख तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान के बारे में बताया एवं बाल विवाह न करवाने हेतु शपथ दिलाई गई। चाइल्ड हेल्पलाइन ने आमजन एवं बच्चों से अपील की आपको इस प्रकार से बाल विवाह होते हुए दिखे या इसकी सूचना मिले तो आप तुरन्त इसकी सुचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल कर बताए। चाइल्ड हेल्पलाइन ऐसे बच्चों की मदद के लिए दिन रात (24 घंटा) तत्पर रहती है। यह एक टॉल फ्री नम्बर है। इस पर कॉल करने का कोई पैसा नही लगता है व इस पर कॉल करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है। बैठक में स्कूल से ओजस्वी परमार प्रधानाचार्य, जिज्ञासा भगोरा उप प्रधानाचार्य, निजामुद्दीन मलिक एवं संजय कुमार प्रजापत माय स्टाफ उपस्थित रहे।

प्रत्येक ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों में आयोजित हुए ग्रामीण सेवा शिविर

-शिविरों में अब तक 10854 मिनी बीज किट किए गए वितरित एवं 2726 पशुपालकों को मिला मंगला पशु बीमा योजना का लाभ

जालोर (रॉयल पत्रिका)। केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन को लाभांवित करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए शनिवार को जिले की 20 ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिले में शुक्रवार को जालोर तहसील की रायपुरिया व सिवणा, आहोर तहसील की पादरली व ओडवाड़ा, सायला तहसील की मेंगलवा व वालेरा, बागोड़ा तहसील की लाखणी व डूंगरवा, भीनमाल तहसील की जैतू व सरथला, जसवंतपुरा तहसील की बूगांव व सीकवाड़ा, रानीवाड़ा तहसील की डूंगरी व मालवाड़ा, सांचौर तहसील की हाडेतर व हरियाली एवं चितलवाना तहसील के जोरादर व भाटकी ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

जिले में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों में ग्रामीणों को मिल रहा लाभ-

जिले में आयोजित हुए ग्रामीण सेवा शिविर के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 2897 पॉलिसियों एवं किसानों को 10854 बीज के मिनी किट, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के 2726 पॉलिसी का वितरण किया गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 3113 नवीन आवेदन किए गए, मूल निवास 1991 तथा जाति प्रमाण-पत्र 2142 जारी किए गए, पालनहार योजना में जोडे गए नवीन आवेदनों की संख्या 86 तथा नवीनीकरण सत्यापन करवाने वाले बच्चों की संख्या 1205 हैं। 9667 गिरदावरी ऐप डाउनलोड किए गए।

जिले में 4 अक्टूबर को इन ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगे ग्रामीण सेवा शिविर-

जिले में गांवों को आत्मनिर्भर, स्वच्छ, जागरूक और सशक्त बनाने तथा जनसहभागिता, सरकारी सेवाओं की सीधी पहुंच और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र ग्रामीणों तक पहुँचाने के उद्देश्य से 17 सितम्बर से ग्राम पंचायतवार ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

मूक बधिर विधवा महिला को मिला संबल

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किये गये ग्रामीण सेवा शिविरों में अनेकों ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है तथा उनकी पुरानी समस्याओं का निदान किया जा रहा है। राहत मिलने पर लाभार्थियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार का आभार जताया जा रहा है। उपखण्ड घडसाना की ग्राम पंचायत 22आरजेडी में शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित हुआ। शिविर में विशेष योग्यजन महिला सरोज देवी उपस्थित हुई। उन्होंने बताया कि ग्रामीण सेवा शिविर की जानकारी उन्हें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत उनके पुत्र लीलाधर के विद्यालय अध्यापक से मिली। वे अपने बेटे के सहारे शिविर में पहुंची। शिविर प्रभारी तहसीलदार रामस्वरूप मीणा के सामने अपनी व्यथा रखी। शिविर में तहसीलदार द्वारा आयोजना विभाग से तुरन्त जनाधार अपडेट करवाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से विशेष योग्यजन महिला के दस्तावेज तैयार करवाकर पालनहार योजना से लाभान्वित किया। विशेष योग्यजन महिला को अब 4250 रूपये की प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिलेगी। सहायता मिलने पर लाभार्थी सरोज देवी, उनके पुत्र लीलाधर एवं सुशील कुमार ने राज्य सरकार का आभार प्रकट किया।

सुरक्षा जवान एवं सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए भर्ती कैंप 7 अक्टूबर से

बून्दी (रॉयल पत्रिका) । भारत सरकार के पसारा एक्ट 2005 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एवं एनडीआरएफ के तहत भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में बूंदी जिले के ग्रामीण और शहरी शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर के पद पर भर्ती हेतु चयन परीक्षा का आयोजन 7 अक्टूबर से किया जाएगा। भर्ती अधिकारी सुरेंद्र पॉटर ने बताया कि ग्रामीण और शहरी शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सिक्योरिटी स्किल काउंसिल आफ इंडिया द्वारा 7 अक्टूबर को रा.उ.मा. विद्यालय तालेड़ा, 8 अक्टूबर को रा.उ.मा. विद्यालय नैनवां, 9 अक्टूबर को रा.उ.मा. विद्यालय केशोरायपाटन, 10 अक्टूबर को रा.उ.मा. विद्यालय हिंडोली, 11 अक्टूबर को रा.उ.मा. विद्यालय बूंदी जिले में 5 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुरक्षा जवान के पद पर सिविल डिफेंस के प्रशिक्षण के लिए इच्छुक बेरोजगार अभ्यर्थी की योग्यता 10 वीं पास, आयु 19 से 40 वर्ष , लंबाई 167.5 सेमी, एवं सुरक्षा सुपरवाइजर 12 वीं पास आयु 21 से 37 वर्ष, लंबाई 170 सेमी होने के साथ ही शारीरिक फिजिकल फिट होना आवश्यक है। इच्छुक बेरोजगार अभ्यर्थी उक्त तिथियों में अपनी 10 वीं पास एवं 12 वीं पास की अंक तालिका, दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं आधार कार्ड के साथ व राजस्थान के अन्य जिले के बेरोजगार अभ्यर्थी भी भर्ती कैंप में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में चयनित अभ्यर्थियों को सिविल डिफेंस का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा 15000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी साथ ही 65 वर्ष तक का स्थाई रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया सुरक्षा जवान को 18000 से 26000 मासिक वेतन पर भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन राष्ट्रीय कृत बैंकों औद्योगिक प्रतिष्ठानों जैसे एसबीआई बैंक, यस बैंक, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, दिल्ली का लाल किला, चांद बावड़ी आवानेरी ,भानगढ़ का किला, कुतुब मीनार, गुड़गांव , हीरो होंडा कंपनी में मानदेय दिया जाएगा अधिक जानकारी के लिए भर्ती अधिकारी के मोबाइल नंबर 9680581471 पर संपर्क कर सकते हैं।

जवाई डैम से सिंचाई के लिए 4900 व पेयजल के लिए मिलेगा 2917 एमसीएफटी पानी मिलेगा

-जवाई बांध जल वितरण समिति की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ निर्णय

पाली (रॉयल पत्रिका)। जवाई बांध से रबी फसल सन् 2025-26 के लिये सिंचित क्षेत्र में नहरी पानी व पेयजल पानी के आंवटन के लिये जल वितरण उपयोगिता समिति की बैठक संभागीय आयुक्त जोधपुर डॉ. प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को जवाई बांध विश्राम गृह में आयोजित की गई । बैठक में इस अवसर पर डॉ सिंह ने सिंचाई व पेयजल के लिए आवश्यक जानकारी लेकर चर्चा की। साथ ही सिंचाई व पेयजल के लिए जल वितरण को लेकर निर्णय लिया गया। इस अवसर पर पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इस बार इंद्रदेव की मेहबानी से जवाई डैम पानी से पूरी तक भरा गया था। इस कारण कई गेटों को खोलना पड़ा। अब बारिश का दौर थमने के बावजूद इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण है। जल वितरण समिति के समस्त लोगों की मौजूदगी में निर्णय लिया गया कि जालोर व पाली जिले में वर्ष 2025-26 की रबी फसल की सिंचाई के लिए 4900 एमसीएफटी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इतनी मात्रा में वर्ष-2017 के बाद पहली बार सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह इस साल पेयजल के लिए भी 2917 एमसीएफटी पानी मिल सकेगा।

बैठक में मंत्री जोराराम कुमावत ने किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि जल का संरक्षण व इसके दुरुपयोग न हो इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने सिंचाई के लिए व पीने के लिए पानी की आवश्यकता के बारे में सभी का पक्ष सुना। बैठक में सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया की जवाई बांध के 7817 एमसीएफटी पानी में से 4900 एमसीएफटी सिंचाई के लिए व पीने के लिए 2917 एमसीएफटी पानी 30 सितंबर-2026 तक दिया जाएगा। यह पानी पेयजल की आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाएगा और इससे पेयजल की भी समस्या नहीं आएगी । इस के लिए विभागीय अधिकारियों से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि इस बार कुल 57 गांवों यानी पाली जिले के सुमेरपुर ब्लॉक के 33 व जालोर जिले के आहोर ब्लॉक के 24 गांवों के 38600 कृषक परिवार लाभांवित होंगे। इस पानी से 38671 हैक्टयेर सिंचाई योग्य भूमि पर रबि की फसलें बोई जा सकेंगी। सर्वसम्मति से हुए निर्णय पर सभी ने हर्ष व्यक्त किया ।

समाज कल्याण सप्ताह 2025 केन्द्रीय कारागृह में मनाया गया अपराधी सुधार दिवस

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। केन्द्रीय कारागृह में समाज कल्याण सप्ताह 2025 के तृतीय दिवस के कार्यक्रम के अंतर्गत अपराधी सुधार दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम केन्द्रीय कारागृह के अधीक्षक आर. अन्तेशवरन के निर्देशन में आयोजित किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक जय प्रकाश ने बताया कि इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित बंदियों को समाज में बदलाव लाने के लिए स्वयं के स्तर से एक शुरूआत करने की बात कही गई। व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता हैं। परिस्थितियों एवं संगत के प्रभाव में आकर व्यक्ति अपराध का दामन थामता हैं। इस मौके पर कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण में सफल रहे बंदियों को कोर्स कम्पिलिशन सर्टिफिकेट देकर उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही उपस्थित प्रतिभागियों को विभाग की ओर से इंडोर गैम्स हेतु कैरम बोर्ड एवं शतरंज भी भेंट किया गया। बंदियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में भी अवगत करवाया गया। साथ ही नशामुक्ति की सामूहिक शपथ का भी आयोजन किया गया। उपस्थित बंदियों में धार्मिक चेतना का संचार करने के लिए हनुमान चालीसा एवं शिव चालीसा का वितरण भी किया गया। सभी बंदियों द्वारा धर्म के रास्ते पर चलने, अपराध एवं बुरी संगत से दूर रहने का आश्वासन अतिथियों को प्रदान किया गया।

विधानसभा क्षेत्र में विद्यालयों के विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृत

-विद्यालयों में मरम्मत व आधारभूत सुविधाओं को मिलेगा सुदृढ़ीकरण

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में विद्यालयों की उन्नति एवं छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने क्षेत्र के विद्यालयों में मरम्मत कार्य हेतु यह राशि स्वीकृत करवाई है। इस राशि से विभिन्न विद्यालयों में आवश्यक मरम्मत एवं विकास कार्य कराए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय खरेखड़ी के लिए 6 लाख रूपए, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेल की डांग मीठा बेरा के लिए 3 लाख रूपए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजयसर के लिए 4 लाख रूपए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माकड़वाली के लिए 12 लाख रूपए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाथीखेड़ा के लिए 5 लाख रूपए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनाड़िया के लिए 3 लाख रूपए, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय वैशालीनगर के लिए 3 लाख रूपए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय महाराणा प्रताप कोटड़ा के लिए 4 लाख रूपए, राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 5 लाख रूपए एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन के लिए 5 लाख रूपए, कुल 50 लाख रूपए की अभिशंषा की गई है। इन सभी कार्यों का क्रियान्वयन समग्र शिक्षा अभियान अजमेर द्वारा किया जाएगा।

प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई को कहा अलविदा

भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई को अलविदा कह दिया है। वह दो दिनों तक मुंबई में रहने के बाद अमेरिका लौट गई हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुंबई में बिताए अच्छे पलों को याद किया है। फैंस को दुर्गा पंडाल में प्रियंका चोपड़ा का लुक काफी पसंद आया। प्रियंका चोपड़ा बनारसी पैटर्न के साथ पर्पल कलर के सूट में दिखीं। एक्ट्रेस ने माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगा रखा था। एक्ट्रेस का देसी लुक फैंस के दिल को भा गया। प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक मुंबई टूर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में एक्ट्रेस पहले अपने स्किनकेयर और मेकअप के बारे में बात कर रही है, वहीं कई स्थानों के साथ वह मां दुर्गा के पंडाल में भी नजर आईं। वीडियो में उन्होंने मुंबई में बिताए दो दिनों की यादें कैमरे में कैद कीं। एक्ट्रेस ने वीडियो के कैप्शन में लिखा,अलविदा मुंबई! वापस आना हमेशा बहुत अद्भुत होता है, भले ही यह एक मिनट के लिए ही क्यों न हो। उत्सव मना रहे सभी लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं। दोबारा आने का वेट करें..।

प्रियंका ने एक्ट्रेस नीलम उपाध्याय को भी दिल से शुक्रिया कहा। उन्होंने लिखा, जब पति मदद के लिए आसपास नहीं थे तो आप थे। वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका को हॉलीवुड एक्शन-कॉमेडी हेड्स ऑफ स्टेट में देखा गया था। फिल्म अमेजन प्राइम पर मौजूद है। एक्ट्रेस एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग कर रही है, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों हैं। एक्ट्रेस सिटाडेल-2, द ब्लफ, जजमेंट डे, एसएसएमबी 29 और कृष 4 में भी दिख सकती हैं।

नई जाना गाने ने मेरी पुरानी यादें कर दीं ताजा: नीरू बाजवा

पंजाबी फिल्मों की सुपरस्टार नीरू बाजवा का नया गाना नई जाना रिलीज हो गया है। यह उनकी आने वाली फिल्म मधानियां का गीत है। इस गाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि इससे उनकी पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। नई जाना एक पंजाबी गीत है, जिसे मन्नत नूर ने गाया है। मनी औजला ने इसका संगीत दिया है। यह गाना आज के जमाने के म्यूजिक के साथ एक पुराने लोकगीत को पेश करता है। इस गाने में एक शादी का सीन दिखाई दे रहा है। इसमें नीरू बाजवा अपने डांस और खूबसूरती से इस गाने की रौनक बढ़ाती दिख रही हैं। यह गाना पंजाबी शादियों की खुशी और उत्साह को दर्शाता है। गाने के बारे में बात करते हुए नीरू बाजवा ने कहा, 'नई जाना' गाने ने बचपन की शादियों में इसे सुनने की तमाम यादें ताजा कर दीं। मधानियां में इसे परफॉर्म करना बेहद सजीव और मजेदार अनुभव था, क्योंकि यह गाना शरारत, प्यार और हंसी का खूबसूरत मेल है। मैं उत्सुकता से इंतजार कर रही हूं कि दर्शक भी इसे देखकर वही खुशी महसूस करें, जो हमें इसे फिल्माते वक्त मिली। नीरू बाजवा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस गाने को शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए उन्होंने हार्ट की इमोजी भी लगाई है। वहीं सिंगर मन्नत नूर ने कहा, यह गाना पूरी तरह से पुरानी यादों को ताजा करता है। पंजाब में हर कोई 'नई जाना' गाने के बारे में जानता है, यह हमारी शादियों और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया तो मेरा ध्यान उस सार को बरकरार रखने के साथ-साथ आज के श्रोताओं के लिए एक ताजगी लाने पर भी था। नई जाना गाना यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है। यह अन्य स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।

अक्टूबर महीने से खास की उम्मीद कर रहीं मलाइका अरोड़ा

शेयर किया इंटरेस्टिंग पोस्ट

फिटनेस डीवा और बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस अपने काम से जुड़ी सारी चीजों को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं। एक्ट्रेस का शो इंडियाज गॉट टैलेंट नए सीजन के साथ टीवी पर वापसी कर रहा है और एक्ट्रेस बतौर जज इसमें नजर आने वाली हैं। हालांकि अब एक्ट्रेस ने ये बताया है कि अक्टूबर महीने में ओ में क्या-क्या ला सकता है। मलाइका अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपडेट किया है और पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा है, मे दा ओ इन अक्टूबर स्टैंड फॉर। पोस्टर पर ओ से शुरू होने वाली काफी चीजें लिखी हैं। मलाइका के द्वारा पोस्ट किए गए इस पोस्टर पर लिखा है, ओपन डोर (रेवेलुशन), ओवरफ्लोइंग ग्रेस, ओवरफ्लोइंग होप, आउटपोरिंग फॉर ब्लैसिंग्स, ओवरकमिंग बैटल, ऑनगोइंग फैथफुलनेस। ये सारी ही चीजें ओ से शुरू होती हैं और अक्टूबर का महीना भी ओ (अंग्रेजी में) से शुरू होता है। उम्मीद करते हैं कि एक्ट्रेस को अक्टूबर के महीने में ये सारी चीजें मिलें। वर्क फ्रंट की बात करें तो मलाइका अरोड़ा का नया शो इंडियाज गॉट टैलेंट 4 अक्टूबर से सोनी लिव पर टेलीकास्ट होगा। शो में मलाइका के अलावा सिंगर शान और नवजोत सिंह सिद्धू नजर आने वाले हैं। इसके अलावा, एक्ट्रेस ने इंडियाज बेस्ट डांसर, मॉडल ऑफ़ द ईयर सीज़न 2, और इंडियाज बेस्ट डांसर-3 जैसे शोज को जज किया है। मलाइका अरोड़ा फिलहाल फिल्मों से दूर हैं और टीवी शोज पर फोकस कर रही हैं। एक्ट्रेस ने खुद को मॉडल शोज और फिटनेस डीवा के तौर पर उभारा है। एक्ट्रेस के नए-नए ब्रांड के फोटोशूट होते रहते हैं। एक्ट्रेस को आखिरी बार फिल्म एन एक्शन हीरो में देखा गया था। इस फिल्म में लीड रोल में आयुष्मान खुराना हैं। फिल्म सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। एक्ट्रेस को डॉली की डोली, हैप्पी न्यू ईयर, और हाउसफुल 2 में देखा गया। मलाइका ने इंडस्ट्री को कई आइटम सॉन्ग दिए हैं, जिसमें पांडे जी बजावे सीटी, छैया-छैया, मुन्नी बदनाम हुई, और अनारकली डिस्को चली शामिल हैं।

12 की उम्र में श्वेता तिवारी ने की थी सिर्फ 500 रुपये के लिए नौकरी, मेहनत से बनीं घर-घर की प्रेरणा

टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। एक्ट्रेस ने टीवी पर तो छाप छोड़ी ही, लेकिन अब सीरीज और फिल्मों में अपना दबदबा बना रही हैं। शनिवार को एक्ट्रेस अपना 45वां जन्मदिन मना रही हैं। एक्ट्रेस की पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ सुर्खियों में रही है। एक्ट्रेस ने 500 रुपये से कमाना शुरू किया और आज लाखों कमा रही हैं। श्वेता तिवारी को सबसे पहले 1999 में आए शो कलीरें में देखा गया था, जिसके बाद सीरियल कसौटी जिंदगी की ने एक्ट्रेस की दुनिया बदल दी, क्योंकि एक्ट्रेस प्रेरणा बनकर घर-घर छा गई। प्रेरणा और अनुराग की जोड़ी आज भी याद की जाती है। श्वेता तिवारी ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि पहले सीरियल की शूटिंग लगातार 72-72 घंटे होती थी। घर जाने का समय नहीं मिलता था और पे चेक भी 30 का नहीं, बल्कि 45 दिन का मिलता था। श्वेता तिवारी ने 12 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था।

ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ 2025

एंजेलिना जोली इफेक्ट के साथ 'हर यात्रा मायने रखती है'

2013 में हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने दुनिया को एक बड़े फैसले से सबको चौंका दिया। उनकी मां (मार्शलीन बर्ट्रेंड) की मृत्यु ओवरी कैंसर से हुई थी। जोली ने टेस्ट कराया और पाया कि उनमें बीआरसीए1 जीन म्यूटेशन है, जो उनके ब्रेस्ट कैंसर के चांस को 87 फीसदी तक बढ़ा रहा था। एंजेलिना ने प्रिवेंटिव डबल मास्टेक्टॉमी (दोनों स्तनों को सर्जरी से हटवाना) करवा लिया। उस समय कइयों ने उनके फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन बाद में हजारों महिलाएं अस्पताल पहुंचीं और टेस्ट कराए। डॉक्टरों का कहना है कि एंजेलिना की इस पहल से जोलि इफेक्ट नाम की एक अवेयरनेस लहर उठी, जिसने अनगिनत जिंदगियां बचाईं। रिसर्च बताती है कि उनके बयान के बाद लाखों महिलाओं ने बीआरसीए टेस्ट करवाने शुरू कर दिए। जोली ने अपने शरीर से जुड़ी बेहद निजी बात का खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स के ओप-एड लेख में किया था। 2013 के इस लेख में उन्होंने एक मां के डर को जाहिर करते हुए लिखा, मैं यह नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को बार-बार वही डर महसूस हो जो मैंने अपनी मां के लिए महसूस किया था। मैंने तय किया कि मैं इस डर को कम करने की पूरी कोशिश करूंगी। जोली की इस ईमानदार कोशिश की दुनिया कायल हो गई।

रियल-लाइफ हीरो सोनू सूद का पंजाब से आशा भरा संदेश, हर परिवार की ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए

शरवरी वाघ ने दशहरे पर शुरू की इम्तियाज अली की फिल्म की शूटिंग

बॉलीवुड अभिनेत्री शरवरी वाघ ने अपनी अगली बड़ी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की। इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली कर रहे हैं। इस फिल्म में वेदांग रैना उनके अपोजिट दिखाई देंगे। दशहरे के शुभ अवसर पर अभिनेत्री शरवरी वाघ ने यह खुशखबरी फैंस के साथ साझा की। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह पूजा के लिए घर पर नहीं आ सकीं। इसके बजाय उन्होंने अपने कमरे में फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ एक छोटी सी पूजा की और फिल्म की शुरुआत की। इस तस्वीर में एक नोटबुक भी रखी है, जिस पर उन्होंने कुछ लिखा था और जिसे ताजा गुड़हल के फूलों से सजाया गया था। इसे शेयर करते हुए शरवरी ने लिखा, आज पूजा के लिए घर पर नहीं आ सकी, इसलिए मैंने अपने कमरे में स्क्रिप्ट के साथ अपनी छोटी सी पूजा की।

पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ को एक महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन गांवों में लोगों की तकलीफें अब भी जारी हैं। अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद, जो संकट के समय में लगातार आशा की किरण बनकर उभरे हैं, उन्होंने हाल ही में गाँव का दौरा किया और हालात का जायज़ा लिया। वहां उन्होंने जो देखा, उससे मदद जारी रखने का उनका संकल्प और मज़बूत हुआ। पंजाब में बाढ़ प्रभावित गांवों के पीड़ितों के साथ खड़े होकर, सोनू सूद ने कहा- आप देख रहे हो कि अभी भी जो बाढ़ के कारण तकलीफें हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और क़रीब 40-45 दिन हो चुके हैं बाढ़ को। और मैं हमेशा कहता आया हूँ ङ्क असली ज़रूरत अब पड़ेगी, क्योंकि पानी का स्तर अभी भी कई जगहों पर बहुत ज़्यादा है। और जो लोग मदद कर रहे हैं ङ्क बचा रहे हैं ङ्क उन्हें इसे जारी रखना चाहिए। गांवों में असली मुश्किलें अब आने वाली हैं, और हर परिवार को जो भी ज़रूरतें हैं, उन्हें हमें पूरा करना है। पंजाब के बाढ़ प्रभावित गाँवों की ज़मीनी हकीकत को बयां करते हुए उन्होंने लिखा, दिन- 45 आइए, ज़रूरतमंदों के लिए एकजुट हों। पंजाब और पूरे देश के लोगों के लिए यह शब्द एक चेतावनी भी हैं और एक आह्वान भी। राहत केवल एक बार की प्रक्रिया नहीं होती यह एक निरंतर दायित्व है। सोनू सूद की पंजाब में उपस्थिति केवल मदद पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि उन आवाज़ों को बुलंद करने के लिए भी है जो मूलभूत सुविधाओं से कटे हुए हैं ङ्क यह याद दिलाने के लिए कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में सोनू सूद संकट के समय में उम्मीद का पर्याय बन गए हैं ङ्क चाहे वो महामारी के दौरान प्रवासी मज़दूरों की मदद हो या अब बाढ़ पीड़ितों की सहायता। उन्होंने बार-बार दिखाया है कि ज़िम्मेदारी और ईमानदारी के साथ प्रभावशाली होना क्या मायने रखता है। पंजाब की इस कठिन घड़ी में उनका काम यह साबित करता है कि राहत केवल दान नहीं ङ्क बल्कि निरंतर करुणा और समर्थन से भरा एक लंबा सफ़र है।

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम लेकर आ रहे तीरंदाजी का नया जोश, एपीएल में हिस्सा लेगी पृथ्वीराज योद्धा

भारत में खेलों का जादू हमेशा से लोगों के दिलों में खास रहा है। हरियाणा की मिट्टी से लेकर देश के कोने-कोने तक, खेलों ने कई युवाओं को प्रेरित किया है। इस कड़ी में तीरंदाजी यानी आर्चरी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी व पूर्व राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज लिन लैशराम की टीम पृथ्वीराज योद्धा आगामी आर्चरी प्रीमियर लीग (एपीएल) में हिस्सा लेंगी। बता दें कि लिन लैशराम पृथ्वीराज योद्धा टीम की सह-मालिक हैं। एपीएल 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी। रणदीप और लिन की यह साझेदारी न केवल खेल को बढ़ावा देगी, बल्कि युवाओं को भी तीरंदाजी जैसे खेल की तरफ आकर्षित करेगी। रणदीप हुड्डा ने कहा, खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हरियाणा में बचपन से ही खेलों की संस्कृति रही है, जहां कुश्ती, हॉकी, और बॉक्सिंग जैसे खेलों ने देश का नाम रोशन किया है। मेरे लिए तीरंदाजी जैसे खेल से जुड़ना एक गर्व की बात है। तीरंदाजी में कई खासियतें होती हैं, जैसे कि ध्यान केंद्रित करना, धैर्य बनाए रखना, और मुश्किल हालात में टिके रहना; ये सभी गुण हरियाणा की खेल संस्कृति से मेल खाते हैं। मेरी पत्नी लिन का इस खेल के साथ गहरा लगाव है, जो हमारी टीम को और मजबूत बनाता है। लिन लैशराम के लिए तीरंदाजी केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक जीवन की यात्रा है। उनके पिता मणिपुर आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही तीरंदाजी की दुनिया की ओर आगे बढ़ाया। लिन ने महज दस साल की उम्र में तीरंदाजी शुरू की और जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगीं। टाटा आर्चरी अकादमी में प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने कई पदक जीते और 1998 में जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी अपने नाम की। हालांकि, चोट के कारण उन्हें प्रतियोगिता से दूरी बनानी पड़ी, लेकिन उनका खेल के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ। अब आर्चरी प्रीमियर लीग में उनका फिर से लौटना उनके लिए एक नई शुरुआत है। इस लीग को लेकर डॉ. विकास गर्ग, जो कि पृथ्वीराज योद्धा टीम के मालिक और एबिक्स ग्रुप के चेयरमैन हैं, ने कहा, आर्चरी प्रीमियर लीग भारतीय तीरंदाजी के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई है।

साभार एजेंसी

राहुल ने लगाया 11वां टेस्ट शतक

भारत बनाम वेस्टइंडीज:

अहमदाबाद, एजेंसी। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। टीम इंडिया ने मैच के दूसरे दिन लंच ब्रेक तक 4 विकेट खोकर 219 रन बना लिए हैं। यहां से टीम इंडिया के पास 56 रन की लीड है। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल टेस्ट करियर का 11वां शतक अपने नाम कर चुके हैं। केएल राहुल 197 गेंदों में 100 रन बनाकर आउट हुए। यह सलामी बल्लेबाज अब तक अपनी पारी में 12 चौके लगा चुका है। राहुल का घरेलू मैदान पर एकमात्र अन्य टेस्ट शतक दिसंबर 2016 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ आया था। फिलहाल, उनका साथ ध्रुव जुरेल दे रहे हैं, जिन्होंने 38 गेंदों में 1 चौके के साथ 14 रन अपने खाते में जुटा लिए हैं।

भारत ने दूसरे दिन की शुरुआत 121/2 के स्कोर के साथ की। मेजबान देश ने पहले सेशन में गिल के रूप में सिर्फ एक ही विकेट गंवाया। टीम इंडिया ने बल्लेबाजी के अनुकूल नजर आ रही इस पिच पर शानदार बैटिंग करते हुए पहले सेशन में 97 रन जुटाए हैं। शुक्रवार को यहां उमस है। ऐसे में गेंदबाज थोड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम को अपना ही फैसला भारी पड़ा। यह टीम पहली पारी में सिर्फ 44.1 ओवर ही खेल सकी। मेहमान टीम महज 162 रन पर सिमट गई।

इंडिया-वेस्टइंडीज टेस्ट:

रवींद्र जडेजा ने भी जड़ा शतक, जुरेल 125 रन बनाकर आउट

विंडीज की टीम पस्त

अहमदाबाद, एजेंसी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. आज (3 अक्टूबर) इस मुकाबले का दूसरा दिन है. भारतीय टीम की पहली पारी चल रही है. भारत का स्कोर 430 रन को पार कर चुका है और उसके 5 विकेट गिरे हैं. रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर नाबाद बैटर हैं. जुरेल ने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाया. वहीं जडेजा भी शतक जड़ चुके हैं. भारत की लीड 260 रनों से ज्यादा की हो चुकी है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमट गई थी. भारत की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की. यशस्वी 36 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं तीसरे नंबर पर उतरे साई सुदर्शन केवल 7 रन बनाकर चलते बने.

संजय बांगर का दावा

वनडे में रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकता है ये भारतीय ओपनर

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व भारतीय कोच संजय बांगर ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल वनडे में रोहित शर्मा के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर 264 रन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बांगर ने 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' पर यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर गिल 45-46 ओवर तक बल्लेबाजी करें, तो उनके पास यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने की पूरी क्षमता है। गिल के दोहरे शतक और शानदार रन-स्कोरिंग फॉर्म को देखते हुए यह भविष्यवाणी भरोसेमंद लगती है।

गिल की वनडे उपलब्धियां: 55 वनडे मैचों में गिल ने 2,755 रन बनाए हैं, जिसमें आठ शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 208 रन है, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 149 गेंदों में बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 19 चौके और नौ छक्के जड़े। गिल अब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा जैसी महान सूची में शामिल हैं।

रिकॉर्ड तोड़ने की संभावना: बांगर का मानना है कि गिल ने पहले भी दोहरा शतक जमाया है और अगर उन्हें लंबी पारी खेलने का मौका मिले तो वह रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उनके मुताबिक गिल की तकनीक, स्ट्राइक रेट और धैर्य उन्हें यह बड़ा रिकॉर्ड हासिल करने के लिए तैयार बनाते हैं। क्रिकेट विशेषज्ञ इसे एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव मिशन मान रहे हैं।

अभिषेक शर्मा और टी20 रिकॉर्ड: बांगर ने युवराज सिंह के 2007 टी20 विश्व कप अर्धशतक के रिकॉर्ड को भी याद किया। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा इस रिकॉर्ड को चुनौती दे सकते हैं। अभिषेक ने हाल ही में एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया, छह पारियों में 314 रन बनाए और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का पुरस्कार जीता।

युवा खिलाड़ियों का भविष्य: बांगर के अनुसार, गिल और अभिषेक दोनों ही भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए कीमती हैं। गिल का रिकॉर्ड तोड़ने का माद्दा और अभिषेक की तेज़ बल्लेबाज़ी टीम इंडिया को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन युवा खिलाड़ियों की मेहनत और क्षमता आने वाले सालों में कई रिकार्ड्स को चुनौती देगी।

सेंथिलकुमार-चोटरानी का निराशाजनक प्रदर्शन, चार्लोट्सविले ओपन के क्वार्टर फाइनल से बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी। मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन और चौथी वरीयता प्राप्त सेंथिलकुमार को सलमान खलील के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मिस्र के खिलाड़ी ने सेंथिलकुमार पर 12-10, 9-11, 11-8, 11-3 से जीत हासिल की। भारत के वेलावन सेंथिलकुमार और वीर चोटरानी अमेरिका के चार्लोट्सविले में आयोजित पीएसए कांस्य स्तर की प्रतियोगिता चार्लोट्सविले ओपन में निराशाजनक प्रदर्शन किया और स्क्वैश के अपने-अपने क्वार्टर फाइन मैचों में हार गए। मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन और चौथी वरीयता प्राप्त सेंथिलकुमार को सलमान खलील के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मिस्र के खिलाड़ी ने सेंथिलकुमार पर 12-10, 9-11, 11-8, 11-3 से जीत हासिल की। सातवीं वरीयता प्राप्त चोटरानी अमेरिका के शीर्ष वरीयता प्राप्त टिमोथी ब्राउनेल से 6-11, 11-9, 1-11, 6-11 से हार गए। सेंथिलकुमार और चोटरानी अब अभय सिंह और रमित टंडन के साथ रविवार से न्यूयॉर्क में शुरू होने वाले 74,000 डॉलर इनामी पीएसए कांस्य स्तर की प्रतियोगिता ओपन स्क्वैश क्लासिक में भाग लेंगे।

Football World Cup:

2026 विश्व कप का आधिकारिक मैच बॉल ट्रियोन्डा लॉन्च, तीन देशों की एकता और जुनून का प्रतीक

ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड), एजेंसी। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो ने लॉन्च के दौरान कहा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक मैच बॉल आ चुका है और यह वाकई शानदार है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए आधिकारिक मैच बॉल ट्रियोन्डा का अनावरण कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में आयोजित होगा और किक-ऑफ में अब केवल नौ महीने का समय बाकी है। फीफा और एडिडास ने मिलकर इस ऐतिहासिक बॉल को तैयार किया है, जो पहली बार तीन देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हो रहे विश्व कप की एकता और जुनून को दर्शाती है।

तीन लहरें का प्रतीक है ट्रियोन्डा

ट्रियोन्डा नाम का अर्थ स्पेनिश भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है तीन लहरें। यह नाम उन तीन मेजबान देशों- कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका को मिलाकर इस वर्ल्ड कप की मेजबानी के जश्न को दर्शाता है। फीफा ने कहा कि यह बॉल सिर्फ एक खेल उपकरण नहीं, बल्कि तीनों राष्ट्रों की साझी ताकत और फुटबॉल प्रेम का प्रतीक है।

फीफा अध्यक्ष इन्फैन्टिनो ने की तारीफ

फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो ने लॉन्च के दौरान कहा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक मैच बॉल आ चुका है और यह वाकई शानदार है। एडिडास ने एक और आइकॉनिक बॉल बनाई है, जिसका डिजाइन अगले साल की मेजबान टीमों- कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका की एकता और जुनून को प्रतिबिंबित करता है। मैं इंतजार नहीं कर पा रहा कि यह खूबसूरत बॉल गोलपोस्ट में जाते हुए दिखे।

जिम्बाब्वे ने 4 साल बाद टी-20 वर्ल्डकप में जगह बनाई

हरारे, एजेंसी। नामीबिया और जिम्बाब्वे ने गुरुवार को टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अफ्रीकन क्वालिफायर में नामीबिया ने तंजानिया को हराया, वहीं जिम्बाब्वे ने केन्या को हराकर द्धुष्ष्ट टूर्नामेंट में जगह बनाई। टूर्नामेंट अगले साल फरवरी और मार्च में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाएगा। नामीबिया ने लगातार चौथे टी-20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। दूसरी ओर, जिम्बाब्वे 4 साल बाद टी-20 वर्ल्ड कप खेलते नजर आएगी। पिछली बार यूगांडा से हारने के कारण टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी थी।

नामीबिया 63 रन से जीती: जिम्बाब्वे के हरारे में 26 सितंबर से अफ्रीकन रीजरन की टीमों के बीच क्वालिफायर टूर्नामेंट खेला जा रहा है। गुरुवार को नामीबिया और तंजानिया में पहला सेमीफाइनल खेला गया। नामीबिया ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट खोकर 174 रन बनाए। टीम से कप्तान जेरार्ड एरासमस ने 55 और रुबेन ट्रम्पलमैन ने 61 रन की पारी खेली। 175 रन के बड़े टारगेट के सामने तंजानिया की टीम 8 विकेट खोकर 111 रन ही बना पाई। टीम से अभिक पटवा ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। नामीबिया के लिए जेजे स्मिट और बेन शिकोंगो ने 3-3 विकेट लिए।

जिम्बाब्वे ने केन्या को हराया : क्वालिफायर का दूसरा सेमीफाइनल केन्या और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए केन्या ने 6 विकेट खोकर 122 रन बनाए। रकेप पटेल ने 47 गेंद पर 65 रन बनाए, बाकी बैटर्स कुछ खास नहीं कर सके। जिम्बाब्वे से ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2 विकेट लिए। 123 रन का टारगेट का जिम्बाब्वे ने 15 ओवर में महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम से ब्रायन बेनेट ने 51 और तादिवनासे मरुमानी ने 39 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और वर्ल्ड कप में एंट्री भी कर ली।

वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप:

मीराबाई चानू ने भारत को दिलाया सिल्वर

फोर्ड (नॉर्वे), एजेंसी। भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम वर्ग में देश को सिल्वर मेडल जिताया है। यह इस प्रतिष्ठित स्पर्धा में मीराबाई चानू का तीसरा मेडल है। साल 2017 की वर्ल्ड चैंपियन ने दूसरी बार सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। उत्तर कोरिया की री सोंग-गम ने कुल 213 किलोग्राम (91 किलोग्राम + 122 किलोग्राम) भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने कुल भार के साथ-साथ क्लीन एंड जर्क में भी नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

थाईलैंड की थान्याथोन सुकचातरोएन के नाम ब्रॉन्ज मेडल रहा, जिन्होंने कुल 198 किलोग्राम (88 किलोग्राम स्नैच + 110 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क) भार उठाया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद अगस्त में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर वापसी की। उन्होंने कुल 199 किलोग्राम (84 किलोग्राम स्नैच + 115 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क) भार उठाया। मीराबाई चानू के 87 किलोग्राम वर्ग में दो प्रयास असफल रहे।

84 किलोग्राम वर्ग में पहला प्रयास भी उनके लिए थोड़ा असहज लग रहा था, लेकिन उन्होंने क्लीन एंड जर्क में अपनी लय वापस हासिल की और तीनों प्रयासों में सफल रहीं। क्लीन एंड जर्क में मीराबाई चानू ने 109 किलोग्राम भार उठाने के बाद 112 किलोग्राम और फिर 115 किलोग्राम भार उठाया। 31 वर्षीय मीराबाई चानू ने अनाहेम में 2017 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने बोगोटा में साल 2022 में 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर अपने नाम किया। 11 अक्टूबर तक चलने वाली वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अगले साल होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाइंग स्पर्धाओं में से एक है। भारत ने इसमें 14 सदस्यीय दल भेजा है। महिला वर्ग में मीराबाई चानू के अलावा, कोयल बार (53 किलोग्राम), बिंद्यारानी देवी सोरोखैबम (58 किलोग्राम), निरुपमा देवी सेराम (63 किलोग्राम), हरजिंदर कौर (69 किलोग्राम), वंशिता वर्मा (86 किलोग्राम), महक शर्मा (86 किलोग्राम+) हिस्सा लेंगी। वहीं, भारत के पुरुष दल का नेतृत्व कॉमनवेल्थ गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवप्रीत सिंह करेंगे।

गगनजीत भुल्लर जकार्ता इंटरनेशनल चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर पहुंचे

जकार्ता, एजेंसी। भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर वर्षा से बाधित जकार्ता इंटरनेशनल चैंपियनशिप के शुरुआती दो दौर में एक समान पांच अंडर 65 का कार्ड खेल शुक्रवार को दूसरे स्थान पर रहे। भुल्लर अब थाईलैंड के पावित टांगकमोलप्रासर्ट (64-65) से सिर्फ एक शॉट पीछे हैं, हालांकि दूसरे दिन का खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। 37 साल के खिलाड़ी ने पहले दौर की शुरुआत ईगल के साथ की, लेकिन अंधेरा होने के कारण पहने दिन का खेल पूरा नहीं कर पाये। उन्होंने शुक्रवार को सुबह अपने पहले दौर को पूरा किया और फिर दूसरे दौर के बाद अपना कुल स्कोर 10 अंडर कर लिया। भुल्लर के एशियन टूर पर कुल 11 खिताब हैं, जिनमें से पांच जीतें उन्होंने इंडोनेशिया में हासिल की हैं। अब वह इस देश में अपनी छठी जीत की तलाश में हैं। अन्य भारतीयों में एस. चिक्कारंगप्पा ने पहले राउंड में 69 और दूसरे में 67 का स्कोर किया। वह संयुक्त 26वें स्थान पर है। राहिल गंगजी, खालिन जोशी, विराज मडप्पा , करणदीप कोचर और अजीतेश संधू , एसएसपी चौरसिया और युवराज संधू का दूसरे दौर का खेल खत्म नहीं हुआ है।

संन्यास के बारे में नहीं सोच रही, मानसिक मजबूती पर ध्यान, बोलीं तीरंदाज दीपिका कुमारी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की अनुभवी तीरंदाज और चार बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अभी संन्यास के बारे में नहीं सोच रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका पूरा ध्यान मानसिक मजबूती और तकनीकी कौशल को निखारने पर है ताकि आने वाले वर्षों में बड़े टूर्नामेंटों में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें।

लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 पर नजर

दीपिका कुमारी ने कहा कि उनका अगला बड़ा लक्ष्य लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 है, जहां उनकी उम्र 34 वर्ष होगी। उन्होंने माना कि यह उनके लिए ÷करो या मरो÷ वाला मौका होगा। दीपिका ने कहा, यह मेरे करियर का अंतिम चरण नहीं है। मैंने संन्यास पर कोई फैसला नहीं किया है। अब तक के अनुभवों ने मुझे मजबूत बनाया है और मैं उसी के सहारे आगे बढ़ रही हूं।

मानसिक और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर: दीपिका ने बताया कि उनकी मौजूदा ट्रेनिंग का फोकस मानसिक और तकनीकी दोनों पहलुओं पर है। उन्होंने कहा, मैं हर तकनीक में महारत हासिल करने की कोशिश कर रही हूं। कई बार महत्वपूर्ण मैचों में मानसिक दबाव की वजह से परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आते थे। अब मैं अलग-अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मानसिक प्रशिक्षण कर रही हूं। उन्होंने माना कि दर्शकों

के सामने खेलने से दबाव तो बढ़ता है, लेकिन यही दबाव खिलाड़ियों को मजबूत बनाता है। दीपिका ने कहा कि तीरंदाजी प्रीमियर लीग जैसे आयोजन खिलाड़ियों को उस दबाव से निपटने का अवसर देते हैं।

कंपाउंड तीरंदाजी के ओलंपिक में शामिल होने से खुश: दीपिका ने हाल ही में ओलंपिक में कंपाउंड तीरंदाजी को शामिल किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे भारत की पदक संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि कंपाउंड तीरंदाजी अब ओलंपिक का हिस्सा है। हमारी टीम पहले ही कई टूर्नामेंटों में पदक जीत चुकी है और बेहद मजबूत है।

तीरंदाजी प्रीमियर लीग को बताया ऐतिहासिक कदम

भारत में पहली बार आयोजित हो रही तीरंदाजी प्रीमियर लीग को दीपिका ने ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा, हम लंबे समय से इस तरह की लीग का इंतजार कर रहे थे। यह तीरंदाजों को घरेलू स्तर पर बड़े मंच का अनुभव देगा और हमारे खेल को नई ऊंचाईयों तक ले जाएगा।

भारत रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-500 खरीदने पर विचार:

-पुतिन के दौरे में हो सकती है नई डील

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों और सूत्रों के मुताबिक, भारत रूस से और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की संभावना तलाश रहा है। इससे पहले भारत ने रूस से पांच S-400 सिस्टम खरीदने का समझौता किया था, जिनमें से तीन भारत को पहले ही मिल चुके हैं। अब नई डील के तहत अतिरिक्त S-400 सिस्टम की खरीद पर बातचीत की जा सकती है। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि इस डील पर चर्चा विशेष रूप से तब हो सकती है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे। ऐसे में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान रक्षा क्षेत्र में बड़े सौदे पर सहमति बनने की संभावना है। यह डील भारत की हवाई रक्षा क्षमता को और अधिक मजबूत करने में मदद करेगी। S-400 ट्राइअम्फ मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे आधुनिक और सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह दुश्मन के हवाई हमलों, जैसे कि क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में ही भेदकर नष्ट कर सकता है। भारत ने इसे अपनी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह सिस्टम पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में सक्षम साबित

हुआ था। यह घटना भारत की हवाई सुरक्षा रणनीति में S-400 की अहमियत को और बढ़ा देती है। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ 5 अरब डॉलर का समझौता किया था, जिसमें पाँच S-400 सिस्टम खरीदने की योजना थी। उस समय अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि यदि भारत इस सौदे को आगे बढ़ाता है तो वह CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) कानून के तहत भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि, भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस सौदे को प्राथमिकता दी और तीन S-400 सिस्टम प्राप्त कर लिए। अब बचे हुए सिस्टम और नए सिस्टम की खरीद के लिए संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत S-500 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी विचार कर रहा है। S-500, S-400 का उन्नत संस्करण है और इसे "प्रमुख आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम" के रूप में देखा जाता है। यह न केवल दुश्मन की मिसाइलों और विमानों से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि उच्च गति और लंबी दूरी तक लक्ष्य को ट्रैक कर उन्हें नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। विशेषज्ञों के अनुसार, S-500 के साथ भारत की हवाई सुरक्षा एक नई ऊँचाई तक पहुँच सकती है। भारत की यह पहल न केवल उसकी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि दक्षिण एशिया में उसकी रणनीतिक स्थिति को भी मजबूती देगी। वर्तमान समय में क्षेत्रीय तनाव और पड़ोसी देशों की उन्नत सैन्य क्षमताओं को देखते हुए, उच्च तकनीक वाले एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। S-400 और S-500 दोनों ही ऐसे आधुनिक मिसाइल सिस्टम हैं जो हवाई हमलों से बचाव में अत्यधिक सक्षम माने जाते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के साथ भारत का यह सहयोग रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका की चेतावनी और CAATSA कानून के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सर्वोपरि रखा है। अब अतिरिक्त S-400 और संभावित S-500 खरीद के साथ, भारत अपनी हवाई सुरक्षा में नई ताकत जोड़ सकता है।

विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि दिसंबर में पुतिन के दौरे के दौरान यह डील दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और गहरा कर सकती है। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण, और रखरखाव जैसी सुविधाओं पर भी बातचीत होने की संभावना है। इससे भारत के मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क को और अधिक मजबूत और व्यापक बनाने में मदद मिलेगी।

मध्यप्रदेश में कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप पर बैन:

-छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के बाद कड़ा एक्शन

नई दिल्ली। तमिलनाडु के बाद अब मध्यप्रदेश में भी कोल्ड्रिफ (Coldrif) और नेक्स्ट्रो-डीएस (Nextro-DS) कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। यह कदम छिंदवाड़ा जिले में 9 बच्चों की मौत के दुखद मामले के बाद उठाया गया है, जिनकी मौत इसी सिरप के सेवन के कारण उनके किडनी फेल होने से हुई थी। छिंदवाड़ा में बच्चों को स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर ये कफ सिरप दिया गया था। बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। इसके लिए पहले तीन जांच टीमों का गठन किया गया और अब इस मामले में एक विशेष जांच टीम (SIT) बनाकर राज्य स्तर पर पूरी जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने X (पूर्व में ट्विटर) पर इस दुखद घटना के संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उन्होंने बताया कि सिरप की बिक्री को पूरे मध्यप्रदेश में तुरंत बैन कर दिया गया है। इसके अलावा, सिरप बनाने वाली कंपनी के सभी अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तुरंत तमिलनाडु सरकार से भी इस मामले की जांच कराने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई और रिपोर्ट के आधार पर सख्त कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के अनुसार, बच्चों में अचानक किडनी फेल होने की घटना ने पूरे इलाके में चिंता पैदा कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस सिरप में कुछ हानिकारक तत्व होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों की किडनी क्षतिग्रस्त हो गई। अब SIT इस मामले में विस्तार से जांच कर रही है कि सिरप में कौन-कौन से रसायन शामिल थे और किन परिस्थितियों में यह बच्चों को दिया गया। इस घटना ने पूरे मध्यप्रदेश में दवा और स्वास्थ्य सुरक्षा के मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की है कि किसी भी दवा या सिरप का सेवन केवल योग्य डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा और बच्चों की जान की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर के अस्पतालों और फार्मेसियों को निर्देश दिया है कि वे कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप की बिक्री पूरी तरह बंद करें और इसके वितरण और उपयोग की सूचना तुरंत दें। यह दुखद घटना बच्चों की सुरक्षा और दवा के नियमन की आवश्यकता को दोहराती है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

महाराष्ट्र में साइक्लोन 'शक्ति' का अलर्ट

-आंध्र और ओडिशा में बारिश और लैंडस्लाइड से मौतें

मुंबई। अरब सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र ने अब चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। श्रीलंका ने इसका नाम 'शक्ति' रखा है। यह मानसून के बाद अरब सागर में बनने वाला इस सीजन का पहला साइक्लोन है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 से 7 अक्टूबर तक इस चक्रवात का असर खास तौर पर मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में देखने को मिलेगा।

महाराष्ट्र पर असर

मौसम विभाग के अनुसार तटीय इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कई जगहों पर हवा की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक पहुंचने का भी अनुमान है। 5 अक्टूबर तक समुद्र में ऊंची लहरें उठने और मछुआरों को खतरे की संभावना जताई गई है। इसलिए मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। हालांकि IMD ने स्पष्ट किया है कि 'शक्ति' का सीधा लैंडफॉल भारत में नहीं होगा। इसके बावजूद तेज हवाएं, ऊंची समुद्री लहरें और भारी बारिश महाराष्ट्र व गुजरात के तटों पर 7 अक्टूबर तक देखने को मिल सकती हैं। मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश के कारण जलभराव, यातायात अव्यवस्था और बिजली कटौती जैसी स्थिति भी बन सकती है।

आंध्र और ओडिशा में आफ़त

साइक्लोन शक्ति के साथ ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक गहरे दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति बन गई है। आंध्र प्रदेश: शुक्रवार को बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। ओडिशा: गजपति जिले में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

तैयारी और चेतावनी

महाराष्ट्र सरकार ने तटीय जिलों के प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। NDRF की टीमें भी तैनात की जा रही हैं ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। मछुआरों को चेतावनी दी गई है कि वे अगले कुछ दिनों तक समुद्र में न जाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह चक्रवात भारत में सीधे नहीं टकराएगा, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष असर भारी बारिश और तेज हवाओं के रूप में दिखेगा। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में इसका सबसे अधिक असर पड़ने की संभावना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों तरफ के दबाव क्षेत्र इस समय भारत के तटीय राज्यों के लिए चुनौती बन गए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात को जहां अरब सागर से उठे साइक्लोन 'शक्ति' से सावधान रहना होगा, वहीं आंध्र प्रदेश और ओडिशा को लगातार बारिश और भूस्खलन की मार झेलनी पड़ रही है।

ट्रम्प चौथी बार फंडिंग बिल पास कराने में नाकाम

-अमेरिका में शटडाउन चौथे दिन भी जारी

वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। अमेरिका में शटडाउन लगातार चौथे दिन भी जारी है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चौथी बार भी फंडिंग बिल पास कराने में नाकाम रहे। सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी द्वारा पेश किए गए इस बिल को केवल 54 वोट मिले, जबकि पारित होने के लिए न्यूनतम 60 वोटों की आवश्यकता थी। वोटिंग के बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसद हॉल से बाहर चले गए, जिससे स्थिति और टकरावपूर्ण हो गई। शटडाउन का सीधा असर सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है। कई विभागों में कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ रहा है और कई सेवाएं ठप पड़ी हैं। इस राजनीतिक गतिरोध ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच की प्रक्रिया धीमी हो गई है, न्यायालयों के कामकाज पर असर पड़ा है और लाखों सरकारी कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं। दरअसल, इस विवाद की जड़ डेमोक्रेट्स की वह मांग है, जिसमें वे कोविड काल के दौरान दी गई टैक्स क्रेडिट्स यानी स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे लाखों अमेरिकियों को सस्ती स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। दूसरी ओर, ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी अतिरिक्त खर्च का विरोध कर रहे हैं और वे इस सब्सिडी को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। यह स्थिति केवल राजनीतिक दलों की खींचतान भर नहीं है, बल्कि इससे अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनता का विश्वास भी प्रभावित हो रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो शटडाउन लंबे समय तक जारी रह सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर गंभीर असर पड़ेगा।

CJI बी.आर. गवई का साफ संदेश:

-बुलडोजर कार्रवाई कानून तोड़ने के बराबर है

नई दिल्ली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि भारत में न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन के सिद्धांत पर आधारित है, और इसमें बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई की कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह बात मॉरीशस में आयोजित सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025 में कही। CJI गवई ने कहा कि सरकार किसी भी परिस्थिति में जज, जूरी और जल्लाद का रोल एक साथ नहीं निभा सकती। कानून की प्रक्रिया में किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तय नियमों और न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत ने हाल ही में ऐसे मामलों में निर्णय दिया है, जिसमें बुलडोजर चलाने जैसे कृत्यों को कानून तोड़ने वाला माना गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बुलडोजर कार्रवाई केवल अपराध को सजा देने का तरीका नहीं हो सकता। यह संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। किसी भी आरोपी को न्याय मिलने से पहले उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है। CJI ने यह बात जोर देकर कही कि कानून का शासन बनाए रखना ही लोकतंत्र की बुनियाद है। बी.आर. गवई ने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर कोई नागरिक कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन इसे न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि "हम किसी भी परिस्थिति में कानून तोड़कर समाधान नहीं निकाल सकते। यह न केवल न्याय प्रणाली के लिए खतरनाक है, बल्कि समाज में अस्थिरता और भय का वातावरण भी पैदा करता है।" CJI ने यह भी उल्लेख किया कि बुलडोजर कार्रवाई अक्सर पब्लिक इमोशन और राजनीतिक दबाव में की जाती है, जो कानून और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी की संपत्ति नष्ट करना या उसका तत्काल निषेध करना केवल न्यायिक आदेश और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही संभव है। इस दौरान CJI ने मॉरीशस में उपस्थित श्रोताओं को याद दिलाया कि कानून का पालन न केवल नागरिकों की जिम्मेदारी है, बल्कि सरकार और प्रशासन की भी है। किसी भी स्थिति में अवैध कार्रवाई करना लोकतंत्र की हत्या के समान है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि सभी नागरिकों को समान और निष्पक्ष न्याय मिल सके। CJI गवई के इन विचारों ने यह साफ कर दिया कि बुलडोजर कार्रवाई जैसी तत्काल और कठोर कार्रवाई कानून के दायरे में नहीं आती। लोकतंत्र में अपराध और कानून के उल्लंघन का मुकाबला करना न्यायपालिका और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन यह जिम्मेदारी संवैधानिक ढांचे और कानून के नियमों के भीतर ही पूरी की जानी चाहिए। इस प्रकार, CJI ने जोर देकर कहा कि भारत में कानून का शासन ही सर्वोपरि है, और किसी भी प्रकार की स्वतःस्फूर्त कार्रवाई कानून तोड़ने के समान है, जिसे लोकतांत्रिक समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

बीजेपी ने की 2 फेज़ में चुनाव कराने की मांग

-जदयू का विरोध: बिहार में एक चरण में चुनाव होना चाहिए

पटना । बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुँच चुकी हैं और इसके लिए चुनाव आयोग (ECI) ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। पटना के होटल ताज में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। बैठक के लिए होटल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। माना जा रहा है कि अगले तीन दिनों के भीतर बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस बैठक का मकसद राज्य की राजनीतिक पार्टियों को चुनाव की तैयारियों, नियमों और मतदान प्रक्रिया से अवगत कराना और उनकी सुझाव व चिंताओं को सुनना है। आयोग ने बैठक से पहले सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की थी कि अधिकतम तीन प्रतिनिधि ही इस बैठक में शामिल हों, ताकि बैठक व्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके। बैठक में सबसे बड़ा चर्चा का विषय चुनाव की फेज़िंग रही। बीजेपी ने अपनी मांग रखते हुए कहा है कि चुनाव दो चरणों में कराए जाएँ। पार्टी का तर्क है कि ज्यादा फेज़ होने पर मतदाताओं को मतदान में परेशानी हो सकती है और उम्मीदवारों को भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। बीजेपी का यह भी कहना है कि बिहार में चुनाव की घोषणा के 28 दिन बाद मतदान कराना उचित रहेगा, ताकि सभी तैयारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके विपरीत, जदयू ने इस पर स्पष्ट विरोध जताया है। जदयू का कहना है कि बिहार में लॉ-एंड-ऑर्डर की स्थिति स्थिर है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की समस्या नहीं है। ऐसे में बिहार में एक ही चरण में चुनाव कराना अधिक उपयुक्त होगा। पार्टी ने यह भी सुझाव दिया कि एक चरण के चुनाव से प्रशासनिक व्यवस्था और चुनाव प्रबंधन आसान रहेगा और मतदाता भागीदारी भी बेहतर होगी। बीजेपी और जदयू के बीच यह मतभेद इस बात को रेखांकित करता है कि चुनाव की फेज़िंग को लेकर राजनीतिक दलों के अपने-अपने दृष्टिकोण हैं। जहाँ बीजेपी अधिक समय और संसाधन बचाने की बात कर रही है, वहीं जदयू प्रशासनिक सहजता और एक ही चरण में पूरी प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दे रही है। इस तरह के मतभेद चुनाव आयोग के सामने एक चुनौती भी पेश करते हैं, क्योंकि आयोग को सभी दलों की बात सुनकर चुनाव की तारीख, फेज़िंग और तैयारियों का अंतिम निर्णय लेना होता है। चुनाव आयोग ने इस बैठक में पार्टियों को यह भी जानकारी दी कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित की जाएगी। आयोग ने मतदाता सूची की अद्यतन स्थिति, ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की उपलब्धता, मतदान केंद्रों की संख्या, सुरक्षा प्रबंध और चुनाव प्रचार के नियमों पर भी विस्तृत जानकारी दी।

जापान को पहली बार मिलेगी महिला प्रधानमंत्री:

-शिंजो आबे की करीबी साने ताकाइची बनीं LDP अध्यक्ष

टोक्यो (एजेंसी)। जापान के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची को अपना नया अध्यक्ष चुना है। जापान मं बहुमत वाली पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनता है, ऐसे में लगभग तय है कि ताकाइची इस महत्वपूर्ण पद पर बैठेंगी। ताकाइची जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी मानी जाती हैं। आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे और उन्हें चीन विरोधी नीतियों का बड़ा समर्थक माना जाता था। यही रुख ताकाइची की राजनीति में भी झलकता है। वे जापान की सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक नीतियों को सख्त अंदाज़ में आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। उनका मानना है कि जापान को चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे। दिलचस्प बात यह है कि ताकाइची देश में पुरुष राजा (एम्परर) के शासन की समर्थक हैं। वे मानती हैं कि जापान के शाही परिवार में केवल पुरुष ही शासन करें, महिला सम्राट या रानी शासन की जिम्मेदारी न निभाएं। यह विचार जापानी समाज में काफी बहस का विषय भी है। उनकी निजी ज़िंदगी भी चर्चा में रही है। साने ताकाइची ने 2004 में साथी सांसद ताकू यामामोटो से शादी की थी।

हमास मान गया ट्रम्प की धमकी से गाजा प्रशासन छोड़ेगा

-बंधक रिहा होंगे, इजराइल ने हमला रोकने का ऐलान किया

वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कड़ी चेतावनी के बाद गाजा युद्ध को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिली है। ट्रम्प ने शुक्रवार को हमास को अल्टीमेटम दिया था कि अगर वह बंधकों को रिहा नहीं करता और गाजा से पीछे नहीं हटता तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। इस धमकी के महज 6 घंटे बाद ही हमास ने ऐलान किया कि वह सीजफायर के लिए तैयार है। हमास ने कहा कि वह ट्रम्प के 20 पॉइंट वाले शांति प्रस्ताव के तहत सभी बंधकों – चाहे वे जिंदा हों या मृत – को रिहा करेगा। साथ ही गाजा का प्रशासन भी छोड़ देगा। हालांकि, हमास के बयान में हथियार डालने का जिक्र नहीं किया गया है। इस पर अभी आगे बातचीत की जरूरत होगी। हमास की घोषणा के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने इजराइल सरकार से कहा कि वह गाजा में हमले बंद करे। इसके जवाब में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि इजराइल ट्रम्प की योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयार है। सरकार ने सेना को आदेश दिया है कि गाजा पर कब्जे की कार्रवाई रोकी जाए और केवल जरूरत पड़ने पर ही जवाबी कदम उठाए जाएं।

मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्त्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शॉपिंग सेंटर, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार्यालय 4312 मोहल्ला नायकों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मों. 08058969180 कार्यालय फोन- 0141-2609886,